ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qku (dk-) : +91(11) 23381428

QDI : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

आवरण कथा : हिमाचल घोषणा पत्र

10 लाख बेरोजगारों को मिलेगा काम........ 7

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का संयुक्तराष्ट्र प्रवास

हमारा सपना सम्पूर्ण विश्व समृद्ध और शांतिप्रिय बनें – आडवाणी........ 10

लेख

वीबीएस का रहस्य

–अरुण जेटली........ 18

आर्थिक सुधार या बंटाधार

–एस. गुरुमूर्ति........ 20

पुस्तक समीक्षा

शिवाजी और सुराज

–विकास आनन्द........ 21

अन्य

भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ........ 23

तेलंगाना : गरीबों तथा वंचितों के साथ भाजपा अध्यक्ष की बातचीत........ 25

गुजरात : जसदण में जनसभा........ 27

मध्यप्रदेश : ''आर्थिक चुनौतियां और समाधान'' विषयक संगोष्ठी........ 28

उत्तर–प्रदेश : महंगाई मिटाओ– कांग्रेस हटाओ– देश बचाओ अभियान........ 29

दिल्ली : 40 दिवसीय जन–आन्दोलन प्रारम्भ........ 30

आवरण परिचय : हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 के निमित्त घोषणापत्र जारी करते प्रदेश भाजपा प्रभारी श्री कलराज मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांताकुमार, मुख्यमंत्री श्री प्रेमकुमार धूमल, राष्ट्रीय महासचिव श्री जे.पी. नड्डा एवं प्रदेश सह–प्रभारी श्री श्याम जाजू।

ऐतिहासिक चित्र

भारतीय जनसंघ के नेताओं के साथ श्री अटल बिहारी वाजपेयी।

कर्तव्यनिष्ठा

काम के प्रति हमारी निष्ठा कैसी हो, इस संबंध में श्री गुरुजी तानाजी मालसुरे के बलिदान की कथा सुनाते थे। महाराष्ट्र में कोंडाना नामक एक प्रसिद्ध किला है। वह मुगलों के अधिकार में था। एक बार माँ जीजाबाई ने उसे जीतकर देने की इच्छा शिवाजी के सम्मुख प्रकट की। बस, शिवाजी ने ठान लिया कि यह किला जीतना ही है।

पर कोंडाना बड़े दुर्गम स्थान पर बना था। उसे जीतना आसान न था। शिवाजी ने अपने साथियों के नामों पर विचार किया, तो उन्हें तानाजी मालसुरे का नाम ध्यान में आया। वे हर प्रकार का खतरा उठाकर भी काम पूरा करने में निपुण थे।

शिवाजी उन्हें बुलाने के लिए किसी दूत को भेज ही रहे थे कि तानाजी अपने बेटे राघोबा के विवाह का निमन्त्रण देने के लिए स्वयं ही वहाँ आ गये। शिवाजी ने सोचा कि तानाजी की व्यस्तता के कारण अब वे स्वयं कोंडाना जीतने जाएँगे। पर तानाजी ने शिवाजी को निश्चिन्त करते हुए कहा – महाराज, राघोबा का विवाह बाद में होगा, पहले कोंडाना किला जीता जाएगा।

तानाजी ने पुत्र के विवाह का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और सेना लेकर आधी रात में को कोंडाना दुर्ग पर धावा बोल दिया। भयंकर युद्ध में तानाजी स्वयं मारे गये; पर किला उन्होंने जीत लिया।

युद्ध के बाद शिवाजी ने कहा – गढ़ आया, पर सिंह गया। तानाजी की स्मृति में उस किले का नाम उन्होंने 'सिंहगढ़' कर दिया। कुछ समय बाद तानाजी के पुत्र का विवाह शिवाजी ने स्वयं बड़ी धूमधाम से किया।

–'श्री गुरुजी बोधकथा' से साभार

व्यंग्य चित्र

साभार : दै. जागरण

साभार : जनसत्ता

इनका कहना है...

"भारत एक सहिष्णु देश है। समता एवं सद्भाव हमारा मूल मंत्र है। हम किसी की सीमा पर आक्रमण नहीं चाहते लेकिन यदि कोई हमारी सीमा पर अतिक्रमण करे, यह भी हमें बर्दाश्त नहीं।"

–नितिन गडकरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

'स्थायी, सद्भावपूर्ण, शांतिप्रिय और न्यायोचित समाज के निर्माण तथा सभी लोगों के उत्कृष्ट जीवन में व्यापक सुधार लाने के लिए व्यापक एवं समावेशी सामाजिक विकास अत्यंत आवश्यक है।"

–लालकृष्ण आडवाणी, अध्यक्ष, भाजपा संसदीय दल

"श्री वीरभद्र सिंह हर तरह से गलत हैं। मामला यह नहीं है कि वह अपना संक्षिप्त नाम 'वीएस' या 'वीबीएस' लिखते हैं। मामला यह है कि क्या इस्पात निर्माता जिसने इन बहीखातों को रखा है, उसमें उनका संक्षिप्त नाम 'वीबीएस' है या नहीं।"

–अरुण जेटली, राज्यसभा में विपक्ष के नेता

"इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता हमें बढ़ती कीमतों के मोर्चे पर देखने को मिलती है। हर चीज़ की कीमत, चाहे वह मटर, दाल, कोयला, तेल, चीनी, चावल, गेहूं– कुछ भी हो, हर चीज; आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है।"

–वेंकैया नायडू, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

संपादकीय

केजरीवाल के पीछे कहीं विदेशी करेंसी का खेल तो नहीं

अन्ना आंदोलन को धूलधूसरित कर अपनी धधकती इच्छाओं की ज्वालामुखी में देश के 'लोकतंत्र' के प्रति अविश्वास पैदा करने की साजिश में लगी अरविंद केजरीवाल की टीम निश्चित ही उन लोगों के इशारे पर खेल रही है जिसे भारतमाता से प्यार नहीं है। केन्द्र सरकार को इस आशय की गंभीर छानबीन करनी चाहिए। केजरीवाल का खेल करेंसी का हो सकता है। अब जानना यह है कि यह करेंसी भारत की है या फिर भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों की। 'सुपारी' किसने दी है यह पता तो डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार को लगाना ही चाहिए।

'केजरीवाल' को शायद यह नहीं पता कि जिस दिन उन्होंने राजनीति में आने और चुनाव लड़ने की घोषणा की उसी दिन उसका सेंसेक्स लुढका ही नहीं, जमीन पर आ गया। स्थिति धीरे-धीरे स्पष्ट होती जा रही है। मुझे ध्यान है कि एक दिन अन्ना ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बारे में कहा था कि इन्हें तो पूना भेज देना चाहिए। लेकिन आज हम कहना चाह रहे हैं कि अन्ना ''अरविंद केजरीवाल'' को कहां रखना चाहेंगे! कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने गुणों से समाज और राष्ट्र में पूजनीय बनना चाहिए, पर कुछ लोगों की गलतफहमी रहती है कि वे दूसरों के दुर्गुणों का बखान कर समाज में सत् पुरुष बनना चाहते हैं। आजकल केजरीवाल यही कह रहे हैं। उन्होंने स्वयं को निष्पक्ष बनाने के लिए जब कांग्रेस के 'वाड्रा' के मुंह पर कालिख पोती तो उन्हें लगने लगा कि कांग्रेस के लोग कहीं यह न कहें कि वह भाजपा के हाथ में खेल रहा है? बस! यह सोचकर भाजपा के राष्ट्रीय श्री अध्यक्ष नितिन गडकरी की जायज बातें, जो वे स्वयं अपने भाषणों में कहते हैं, को उन्होंने नमक-मिर्च और मसाला लगाकर बताना शुरू कर दिया!

यहां से शुरू हुआ केजरीवाल के निष्पक्ष बनने का सिलसिला। श्री नितिन गडकरी जिस दिन भाजपा के अध्यक्ष बने, उसी दिन से अपने बारे में, अपने कार्यों के बारे में स्वयं बताते हुए सहकारिता के माध्यम से सहयोग करने और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की बातें बताने लगे। ''केजरीवाल'' ने कौन सी नई बातें बतायीं? जो भी बातें अरविंद केजरीवाल ने नितिनजी के बारे में कहीं, उसकी हवा तो स्वयं केन्द्रीय मंत्री शरद पवार ने यह कहकर निकाल दी कि ''नितिन गडकरी ने कोई गलत काम नहीं किया।'' यह टिप्पणी केजरीवाल के मुंह पर करारा तमाचा था। वहीं नितिनजी ने यह कहकर कि उन पर लगाए गए आरोपों की जांच हो जाए, केजरीवाल की अनैतिकता और साजिश की पोल खोल दी।

श्री शरद पवार ने सच कहा तो उनकी बेटी सुप्रिया को कठघरे में खड़ा कर दिया। यहां यह बात साफ हो गई कि राजा हरिश्चन्द्र की भूमिका वाले 'केजरीवाल', जिसे हम पहले दिन से समझ रहे थे, की पोल खुल गई। केजरीवाल वैसे निकले जैसे- सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे, जो अन्ना का नहीं वह देश का क्या होगा? विदेशी धन से देशी लोकतंत्र का गड्ढ़ा खोदने में लगे केजरीवाल शायद यह भूल गए कि भारत के जन-गण-मन की आत्मा की लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था है। अत: ऐसे परिपक्व नागरिकों को अरविंद केजरीवाल इन छोटे-मोटे अनर्गल निराधार आरोपों से कमजोर नहीं कर सकते।

''केजरीवाल'' है क्या? क्या उनके बारे में लोगों को नहीं मालूम कि वह है अन्ना आंदोलन का 'ब्लैक मेलर'' या यूं कहें कि अन्ना के साथ विश्वासघात करने वाला! जिस 'अन्ना' ने अरविंद केजरीवाल को अपने आंदोलन के आंचल का दूध पिलाकर बड़ा किया, उसने उसी 'अन्ना' का साथ छोड़ अपना नाम निश्चित ही देश के विश्वासघातियों में शामिल कर लिया। एक विश्वासघाती को

क्या दूसरों पर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार है?

''अरविंद केजरीवाल' चाहता है कि उसकी हरकतों पर देश के लोग गुस्सा उतारें और जाने-अनजाने में उसकी कहीं पिटाई हो जाए, जिससे भारत की जनता की उसे भावनात्मक समर्थन मिलना शुरू हो जाए। वह उसी बात की बाट जोह रहा है। लेकिन उसे शायद यह नहीं पता कि उन जैसे कितने आए और कितने गए पर भारत का परिपक्व लोकतंत्र कभी ओछी हरकतें नहीं करता। यह गांधी (सोनिया गांधी का नहीं) का देश है जहां लंगोटी लगाकर बापू ने अंग्रेजों को जनशक्ति के बूते भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। संगीन आरोपों और साजिशों के ढेर पर बैठकर विदेशी धन से स्वदेशी भावना की लड़ाई नहीं की जा सकती। वो तो भला हो उन चैनलों का जिन्होंने समाज के इन ''कुकुरमुत्तों'' को मुंह लगाकर अपने चैनलों का कीमती समय बर्बाद किया और जनता को भी गुमराह किया। पर भला हो इस देश की जनता जनार्दन का जो सच और साजिश में, भ्रम और यथार्थ में, भ्रांति और क्रांति में, अनशन-आंदोलन और प्रोपगंडा में अंतर समझती है। ''खुल गई पोल और पिट गई ढोल!'' खाल ओढ़कर शेर की भूमिका अदा करना और जमीन पर जंगल में रहते हुए अपना खौफ़ बनाए रखना, सामान्य बातें नहीं होतीं। ''शेर की खाल में... निकला'' खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

पर देश का कीमती समय, अमूल्य मानव संसाधन और देश को भावनात्मक ब्लैकमेल करने वाला भांडा बहुत शीघ्र फूट गया। यह व्यक्ति के लिये, राजनीति के लिये, राजनैतिक दलों के लिए कितना अच्छा हुआ, यह तो पता नहीं पर इतना अवश्य गर्व से कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिये, उसकी मर्यादा के लिये ''केजरीवाल'' की पोल खुलना अच्छा ही रहा। ■

जीवेम शरदः शतम्

जन्म दिवस : 8 नवम्बर 1927

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी के जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली, पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री एम वेंकैया नायडू और श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल एवं कमल संदेश के सम्पादक श्री प्रभात झा सहित अन्य सभी नेतागण एवं कार्यकर्ता श्री लालकृष्ण आडवाणी की दीर्घायु की कामना करते हुए अभिलाषा रखते हैं कि वे चिरकाल तक पार्टी एवं राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहें।

कमल संदेश परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों को अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

10 लाख बेरोजगारों को मिलेगा काम

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 4 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश में भाजपा ने 22 अक्टूबर को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने अपने इस चुनाव घोषणापत्र में समाज के लगभग हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है। पार्टी का चुनाव घोषणापत्र मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, पार्टी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी कलराज मिश्र, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और प्रदेश भाजपा सह प्रभारी श्याम जाजू ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में जारी किया। पार्टी ने सत्ता में आने पर चुनाव घोषणा पत्र को राज्य का नीति पत्र घोषित कर लागू करने का वादा किया है।

चुनाव घोषणा पत्र में राज्य के सभी परिवारों को चरणबद्ध ढंग से इंडक्शन चूल्हा देने का वायदा किया गया है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी ने ये वादा लोगों को रसोई गैस सिलेंडर के बढ़े दामों से राहत देने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली काफी सस्ती है ऐसे में इंडक्शन चूल्हे से लोगों को महंगाई में काफी राहत मिलेगी और रसोई गैस पर निर्भरता कम होगी। पार्टी ने आगामी पांच सालों के दौरान राज्य में 10 लाख लोगों को रोजगार सृजित करने का भी वादा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में सरकारी क्षेत्र में पचास हजार से अधिक नई भर्तियां की और लगभग एक लाख लोगों को निजी क्षेत्र में

रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा कि आगामी पांच सालों में सरकारी और निजी क्षेत्र में पांच लाख रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसके अलावा स्वरोजगार के माध्यम से पांच लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जाएंगे। इसके लिए युवाओं को एक लाख रुपए तक का ऋण दो प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। पार्टी ने प्रदेश में दैनिक मजदूरी 150 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए करने का भी वायदा किया।

भाजपा ने प्रदेश में चल रही पॉलीहाउस योजना को अगले तीन वर्षों तक जारी रखने की भी वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि 2012 से 2017 के लिए नई किसान, बागवान नीति बनाई जाएगी और प्रदेश में कृषि तथा बागवानी के उत्पादों तथा उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कृषि व बागवानी विश्वविद्यालयों के माध्यम से व्यापक योजना तैयार की जाएगी। पार्टी ने निर्धारित समय पर कृषि ऋण वापस करने वाले किसानों के लिए ब्याज दर केवल दो प्रतिशत ही तय करने का भी वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि 4 प्रतिशत ब्याज दर वाले इन ऋणों का 2 प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकार देगी। किसानों और बागवानों के उत्पादों को जिला मुख्यालयों से मंडियों तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने जिला मुख्यालय और मंडियों के बीच एसी गाड़ियां चलाने का भी वादा किया। साथ ही यह भी कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए टैंक बनाने पर सब्सिडी दी जाएगी। पार्टी ने छोटे व्यापारियों के लिए वैट की सीमा आठ लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपए करने का भी वायदा किया। साथ ही यह भी कहा है कि व्यापारियों के लिए जारी बीमा योजना आगे भी जारी रहेगी तथा इसमें वकीलों, टैक्सी चालकों और ट्रक चालकों को भी शामिल किया जाएगा।

पार्टी ने प्रदेश के सभी अनुबंध कर्मचारियों को पांच साल में ही नियमित करने की भी घोषणा की। साथ ही ये भी वायदा किया कि कालेज लैक्चररों को प्रोफेसर के पद तक पदोन्नति दी जाएगी। पार्टी ने कंप्यूटर टीचरों के लिए नीति बनाने और पीएटी तथा पीटीए शिक्षकों के नियमितिकरण के लिए नीति बनाने का भी वादा किया। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 65 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनरों की पेंशन में पांच प्रतिशत, 75 वर्ष की आयु पूरी करने पद 10 प्रतिशत, 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर 20 प्रतिशत तथा 100 वर्ष की आयु पूरी करने पर 100 प्रतिशत पेंशन वृद्धि देने का भी वादा किया।

भाजपा ने राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पांच साल में एक बार मुफ्त तीर्थ यात्रा का भी वादा किया है। पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाजपा के सत्ता में आने पर राज्य के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पांच सालों में पांच-पांच सामुदायिक केंद्रों का निर्माण करेगी। भाजपा ने राज्य में जलविद्युत दोहन की क्षमता 12 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 20 हजार मेगावाट करने, पानी को मिनरल मानते हुए केंद्र से वाटर सेस का प्रावधान करने, प्रदेश में 1990 से पहले बनी पनविद्युत परियोजनाओं से भी प्रदेश के लिए 12 प्रतिशत रॉयल्टी हासिल करने और नई परियोजनाएं स्थापित करने को प्राथमिकता देने का भी वादा किया है। भाजपा ने लोगों को अधिकाधिक मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते 90 फीसदी से अधिक मतदान वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने का भी अपने चुनाव घोषणापत्र में वादा किया है। पार्टी ने पब्लिक सर्विस गारंटी अधिनियम को जनता से जुड़े सभी सार्वजनिक कार्यालयों में लागू करने, आवश्यकतानुसार नए जिलों का गठन करने, जहां शपथ पत्र आवश्यक नहीं होगा वहां इसकी अनिवार्यता समाप्त करने, लोकमित्र केंद्र पंचायत स्तर पर स्थापित करने, प्रत्येक जिले में भ्रष्टाचार निरोधक केंद्र स्थापित करने, जमीन का अधिग्रहण केवल जनहित में ही करने, रिटेंशन पॉलिसी को क्रियान्वित करने योग्य बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले निर्माण कार्यों के लिए अलग से ग्रामीण इंजीनियरिंग विंग स्थापित करने, युवाओं को रोजगार पाने के योग्य बनाने के लिए कौशल विकास की वृहद् योजना बनाने और खेलों के लिए बजट दोगुणा करने का भी वायदा किया।

भाजपा ने अटल स्कूल यूनीफार्म योजना में वर्दी के साथ छात्रों को अब बैग और एक-एक डिक्शनरी देने, टांडा तथा आईजीएमसी शिमला में एमबीबीएस सीटों की संख्या 200 से बढ़ाकर 400 करने, प्रदेश में विधि और संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, निजी विश्वविद्यालयों को भूमि प्रयोग परिवर्तित करने की अनुमति न देने, सभी सरकारी अस्पतालों में सभी वर्गों के रोगियों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाने, 175 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चौबीसों घंटे प्रसव सुविधा उपलब्ध करवाने, पांच नए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने, अटल बिजली बचत योजन को जारी रखने का भी चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है।■

भाजपा महिला मोर्चा

गर्भवती महिलाओं को ट्रेन में मिलेगी निचली बर्थ

गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं का अब ट्रेन में सफर आसान हो सकेगा। लंबी दूरी की ट्रेन में रेलवे उन्हें निचली बर्थ देने में वरीयता देगा। इस सुविधा का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। फिलहाल, लोकल ट्रेनों में विकलांगों के लिए आरक्षित डिब्बों में गर्भवती महिलाओं को सफर करने की अनुमति है।

सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक सुबोध जैन ने बताया कि आरक्षण फॉर्म में गर्भवती महिला यात्रियों के लिए अलग से कॉलम बनाया गया है। एहतियातन उनसे अपने मेडिकल पेपर साथ रखने के लिए कहा गया है। संबंधित अधिकारियों के मांगे जाने पर उन्हें ये दिखाने होंगे। सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन बुकिंग पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसके लिए रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर गर्भवती होने के मेडिकल पेपर दिखाने होंगे।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय से मुलाकात कर इस बाबत मांग उठाई थी।

उन्हें बताया गया था कि पहले ही वरिष्ठ नागरिकों के साथ गर्भवती और 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं का कोटा है। इसके तहत इन श्रेणियों में आने वाले यात्रियों को एसी 3, एसी 2 और स्लीपर क्लास में प्रति कोच दो निचली बर्थ आरक्षित होती हैं।

हालांकि, जोनल रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति (जेडआरयूसीसी) की अंतिम बैठक में ईरानी ने अपनी मांग की स्थिति का जायजा लिया। इस बार उन्हें बताया गया कि रेलवे इसे लागू करने की प्रक्रिया में है। ईरानी जेडआरयूसीसी की भी सदस्य हैं। ■

केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने पर देश की सभी सीमाएं सील होंगी : नितिन गडकरी

यह यात्रा इस नारे के साथ प्रारम्भ की जा रही है ''युवा मोर्चा का संदेश - अब न कटेगा - अब न बंटेगा, भारत देश।''

भारत एक सहिष्णु देश है। समता एवं सद्‌भाव हमारा मूल मंत्र है। हम किसी की सीमा पर आक्रमण नहीं चाहते लेकिन यदि कोई हमारी सीमा पर अतिक्रमण करे, यह भी हमें बर्दाश्त नहीं।'' उक्त उद्‌गार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 18 अक्टूबर 2012 को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित शहीद श्रद्धांजलि यात्रा के शुभारम्भ अवसर पर उपस्थित जन-समूह को सम्बोधित करते हुए कहे।

श्री गडकरी ने आगे कहा कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाना चाहता है। चीन और भारत में शांति तथा सौहार्द कायम रहे। इनमें परस्पर साहित्य, कला, इतिहास एवं विरासत हम दोनों देशों में महत्वपूर्ण है। देश में सर्वाधिक विकास हो, देश भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इसी के साथ देश की सुरक्षा करना भी हम सब का परम कर्त्तव्य है। श्री गडकरी ने धर्मनिरपेक्षता को व्याख्यायित करते हुए कहा कि प्रशासन, मीडिया, न्यायपालिका एवं सेना ये सब धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं लेकिन व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। भाजपा सभी धर्मो का सम्मान करती है। देश में सभी धर्मो हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आदि के लोग एक साथ मिलकर रहें और देश के विकास एवं प्रगति में साथ दें, यही भाजपा का उद्‌देश्य है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने पर देश की सभी सीमाएं सील होंगी। श्री गडकरी ने विदेशी घुसपैठ पर कहा कि विदेशी घुसपैठ भी कांग्रेस का एफ.डी.आई है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ''शहीद श्रद्धांजलि यात्रा'' 1962 के उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकाली जा रही है जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। यात्रा का मकसद यह भी जानना है कि उस समय क्या स्थितियां और क्या परिस्थितियां थीं और आज 50 वर्षो बाद हमारी क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है व हमारी क्या तैयारियां हैं तथा हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं। साथ ही सीमा पर तैनात नौजवानों में यह विश्वास पैदा करना कि देश का सारा नौजवान आपके साथ है।

यह यात्रा इस नारे के साथ प्रारम्भ की जा रही है ''युवा मोर्चा का संदेश - अब न कटेगा - अब न बंटेगा, भारत देश।'' कार्यक्रम में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एन. एस. मलिक ने कहा कि यह एक अघोषित युद्ध था जिसकी न प्रारम्भ की घोषणा की गई और न अंत की। आज भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह संघर्ष जारी है।

यात्रा के शुभारम्भ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 1962 युद्ध के दो पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया तथा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री किरन रिजीजू ने पुनः भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती विजया चक्रवर्ती व राष्ट्रीय महामंत्री श्री तापिर गाव, श्रीमती किरण महेश्वरी तथा असम प्रदेश के अध्यक्ष श्री रंजीत दत्ता आदि भी उपस्थित थे।■

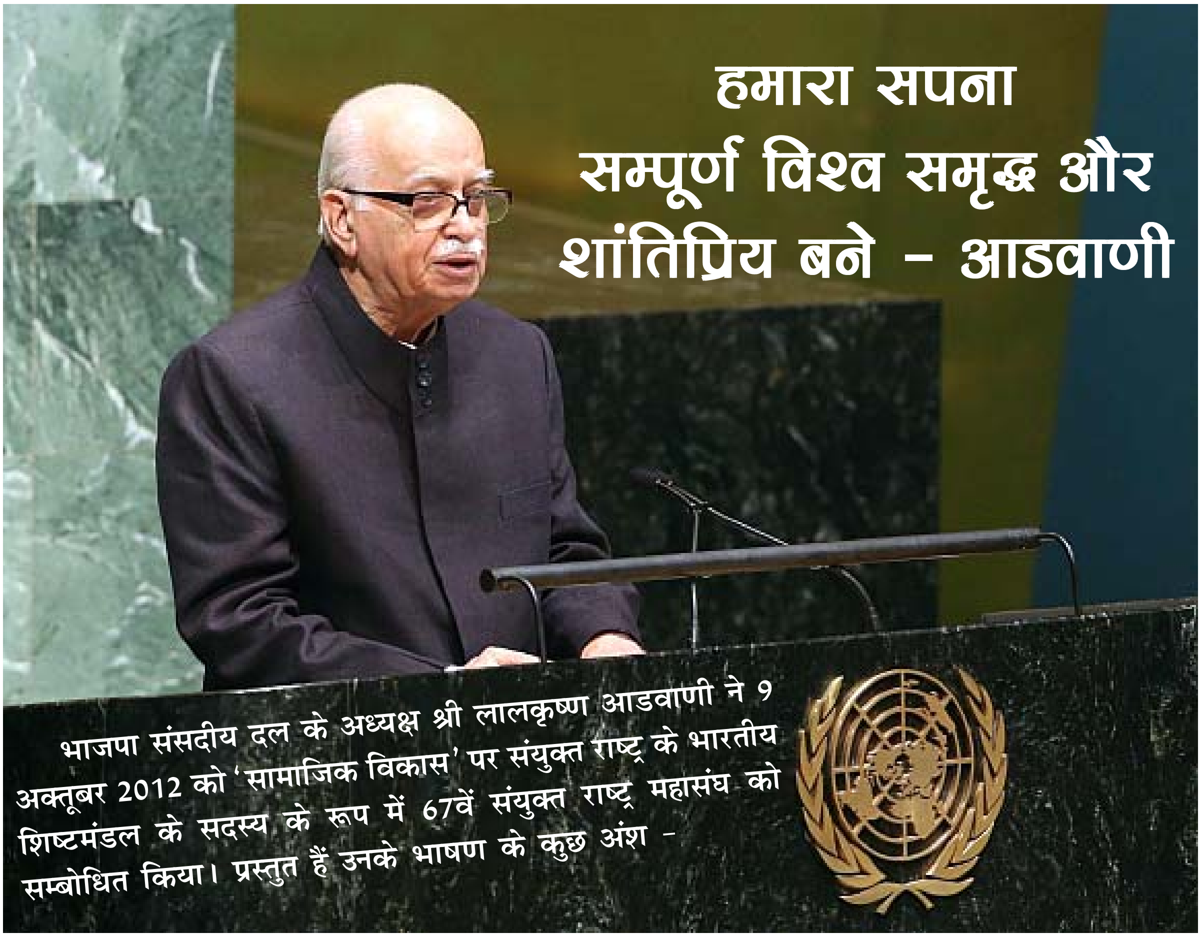

हमारा सपना सम्पूर्ण विश्व समृद्ध और शांतिप्रिय बने – आडवाणी

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने 9 अक्तूबर 2012 को 'सामाजिक विकास' पर संयुक्त राष्ट्र के भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में 67वें संयुक्त राष्ट्र महासंघ को सम्बोधित किया। प्रस्तुत हैं उनके भाषण के कुछ अंश –

मि. चेयरमैन,

प्रारम्भ में ही, मैं भारतीय शिष्टमंडल की ओर से आपको और ब्यूरो के अन्य सदस्यों को आपके निर्वाचन और इस महत्वपूर्ण कमेटी की अध्यक्षता करने पर बधाई देना चाहता हूं।

मैं आपको इस कमेटी के विचारविमर्श और कार्यों में अपने शिष्टमंडल का पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान करने का आश्वासन देता हूं।

हम एजेण्डा मद के अन्तर्गत विभिन्न रिपोर्टों के लिए सेक्रेटरी-जनरल को धन्यवाद देना चाहते हैं और हम अंडर-सेक्रेटरी जनरल फॉर इकॉनामिक एंड सोशल अफेयर्स पर उनके वक्तव्य पर भी उनका धन्यवाद करना चाहते हैं।

भारत 'जी77'' की ओर से अल्जीरिया में दिए गए वक्तव्य के साथ सहमत है।

मि. चेयरमैन,

1995 में वर्ल्ड सोशल सम्मिट (विश्व समाज शिखर सम्मेलन) के समय से ही समाज विकास के तीनों प्रमुख स्तम्भों अर्थात्, निर्धनता उन्मूलन, सम्पूर्ण रोजगार संवर्धन और समुचित कार्य एवं सामाजिक एकता में प्रगति हुई है। फिर भी, इन सभी क्षेत्रों में बहुत सी चुनौतियों को अब भी पार किया जाना है।

सेक्रेटरी-जनरल की रिपोर्ट में यह बात सही ही कही गई है कि बहुत से देशों में आय-निर्धनता में कमी आई है, फिर भी इन देशों को शिक्षा, खाद्य और अन्य बुनियादी वस्तुओं तथा सेवाओं में प्रमुख चुनौतियों का सामना करना अभी तक जारी है। इसके अलावा समस्त विकासशील देशों में बेरोजगारी, खाद्य एवं ऊर्जा की चिंताएं बनी हुई है। विश्व में गम्भीर आर्थिक स्थिति के जारी रहने से विकासशील देशों की क्षमताएं और अधिक सीमित बन गई हैं जिससे विश्व आर्थिक प्रणाली में आघातों और दुर्बलताओं से जूझना एक मुश्किल काम हो गया है।

अतः, यह बहुत जरूरी है कि हम सब सामूहिक रूप से मांग और रोजगार पैदा करने को प्रोत्साहित करने के लिए विकासोन्नत नीतियों को अपना कर

चलें। आज जब एक बिलियन से अधिक लोग अत्यंत निर्धनता और भूख का जीवन बिता रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम 'इंक्लूसिज ग्रोथ' को प्राथमिकता देना नहीं भूल सकते हैं।

रियो20सम्मिट में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निर्धनता के विश्व की सबसे बड़ी चुनौती मानते हुए पोषणीय विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता स्वीकार की थी।

2015 के बाद विकास एजेण्डा का जारी रहना अत्यंत आवश्यक है जिससे निर्धनता-उन्मूलन को प्राथमिकता दी जाए और अगले कुछ वर्षों में मिलेनियम डेवलेपमेंट लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाए।

मि. चेयरमैन,

हम सेक्रेटरी-जनरल से सहमत है कि बहुत से विकासशील देशों में जिस प्रकार की घरेलू वित्तीय घाटों का सामना करना पड़ रहा है, उसके समाधान के लिए और अधिक व्यावहारिक प्रयास करना आवश्यक है।

इन देशों को कारगर ढंग से घरेलू संसाधन जुटाने होंगे, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्व प्रबंधन, गवर्नेंस सुधार, अधिक कारगर कराधान नीतियां और वित्तीय समावेश मजबूत करने जैसे उपाए शामिल हैं।

इसके अलावा, भ्रष्टाचार पर युद्धस्तर पर काम करना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की गहन आवश्यकता है। हालांकि यह ऐसी समस्या है जो विकासशील और विकसित दोनों प्रकार के देशों में फैली हुई है, परन्तु विकासशील देशों पर इसका प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है क्योंकि इसके कारण सेवा प्रदान करने और लोगों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। बिना हिसाब-किताब वाले धन का सृजन या ब्लैकमनी का भी प्रभाव अर्थव्यवस्था की सीमित वृद्धि और उत्पादनकारी क्षेत्रों में निवेश पर बहुत भारी पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है।

यूएन कंवेंशन अगेंस्ट करप्शन के मामले में सभी देशों को इसमें परिशोधन करना आवश्यक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सार्थक सहयोग करना भी आवश्यक है जिससे विदेशों में जमा भ्रष्टाचार के माध्यम से चुराए गए धन और सम्पत्ति को वसूला जा सके।

कार्यान्वयन और प्रवर्तन के अन्तर को समाप्त करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, इस बात को देखते हुए जी-20 के नेताओं ने मैक्सिकों में हाल की अपने शिखर सम्मेलन में यह तय किा कि जो लोग रिश्वत लेते हैं और मांगते हैं तथा जो रिश्वत देते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। इन देशों ने इस बात पर भी सहमति प्रगट की कि जी-20 के अधिकार क्षेत्रों में सम्पत्तियों की तलाश की जाए और भ्रष्ट राशि को सुरक्षित माने जाने वाले देशों में जाने से रोका जाए और इस प्रकार की चुराई सम्पत्तियों की वसूली की जाए।

घरेलू संसाधन जुटाने के प्रयासों को बढ़ाकर औपचारिक विकास सहायता से पूरा किया जाए जो विकसित देशों द्वारा किए गए वायदों से काफी नीचे गिरती जा रही है।

मि. चेयरमैन,

भारत में, लोगों के सशक्तिकरण, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के आधार पर समावेशी विकास की उपलब्धि ने गुड गवर्नेंस, और सामाजिक क्षेत्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य, दक्षता प्रशिक्षण, सस्ते आवासों पर प्रमुख ध्यान दिया गया है। क्योंकि भारत की 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, इसलिए विशेष रूप से ग्रामीण विकास पर अधिक बल दिया गया है। ऐसे कई कार्यक्रम हैं, जिससे महिलाओं और कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना विश्व का सबसे बड़ा काम के बदले नकद कार्यक्रम है, जो प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार देकर 53 मिलियन ग्रामीण गरीब लोगों को सहायता देता है। इसमें कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। इस कार्यक्रम से सामाजिक विषमताओं, ग्रामीण लोगों को अधिकार-सम्पन्न, ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और आर्थिक विकास में नए ढंग से मदद की है।

शिक्षा के क्षेत्र में पहल करने से भारत ने लड़कों और लड़कियों के पढ़ने के मामले में प्राइमरी स्तर पर लगभग पूर्णता प्राप्त कर ली है और इससे मिडिल और हायर एजुकेशन के बीच लिंग भेद का अंतर समाप्त हो गया है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार से जीवन आयु में वृद्धि हुई है, बच्चों की रोगक्षमता की दर बढ़ी है और शिशुओं एवं मातृत्व मृत्यु दरों में पर्याप्त कमी आई है।

निर्धनता शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल सम्बन्धी परफोर्मेंस सूचकांक के रूप में आर्थिक विकास के हमारे लक्ष्य सफल रहे हैं। ये लक्ष्य राज्य क्रमों में अलग-अलग है, जो इन अधिकांश कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करते हैं और ये राज्य इन कार्यक्रमों पर नजर रखते हैं, आकलन और सुधार करते हैं।

मि. चेयरमैन,

भारत ने वैध रूप से अक्षम व्यक्तियों के लोगों की सहायता का व्यापक

शेष पृष्ठ 20 पर

'भाजपा ऐसे सुधारों के प्रति वचनबद्ध, जो राष्ट्रहित में हों'

राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली द्वारा आर्थिक प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई पर प्रस्तुत प्रमुख बिन्दु

भाजपा आर्थिक सुधारों के प्रति वचनबद्ध है, जो राष्ट्रीय हित में हों। आखिर, किसी भी बदलाव का मतलब सुधार से नहीं होता है। इस प्रकार से सुधारों से सम्भव है कि वे राष्ट्रीय आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने वाले हों। भाजपा ने मल्टी-ब्रांड रिटेल को एफडीआई में लाने के लिए कई कारणों से विरोध किया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. पहली बात तो यही है कि इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां खत्म हो जाएंगी। घरेलू खुदरा बाजार स्थानीय रूप से इनका प्रमुख साधन है। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्ड रिटेल संसाधनों से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग का ह्रास होगा। यह बात और भी प्रमुख बन जाती है जब हम देखते हैं कि भारत ने महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार नहीं किए हैं।
2. इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्ड रिटेल से अतिरिक्त रिटेल नौकरियां नहीं बन पाएंगी, इससे तो वर्तमान नौकरियों का ही विस्थापन हो जाएगा।
3. भारतवासियों का केवल 18 प्रतिशत ही स्ट्रक्चर्ड नौकरियों का भाग बनता है, बाकी 51 प्रतिशत भारत की जनता सेल्फ-एम्पलायड (स्वरोजगार) के दायरे में आती है। कृषि क्षेत्र के साथ-साथ, खुदरा व्यापार स्व-रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत में स्ट्रक्चर्ड

इंटरनेशनल रिटेल से नौकरियों को भारी नुकसान पहुंचेगा।
4. फ्रेग्मेंटेड (विखंडित) बाजार कंसोलिडेटेड (समेकित) बाजारों की तुलना में अधिकतम हित साधते हैं। एफडीआई से रिटेल (खुदरा) बाजारों का समेकन हो जाएगा और इससे उपभोक्ता के हित सीमित रह जाएंगे। एफडीआई के रिटेल में खोलने के पहले 12 वर्षों में थाईलैण्ड यह बात देख चुका है कि जहां उपभोक्ता बाजारों का 38 प्रतिशत भाग तीन बड़े-बड़े रिटेलरों के हाथ में चला गया।
5. चीन के बारे में प्राय: जो उदाहरण दिया जाता है, वह गुमराह करने वाला है। चीन की अर्थव्यवस्था प्रमुखतया कम कीमत पर आधारित है और चीन बड़े-बड़े रिटेलरों का भारी आपूर्तिकर्ता है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि चीन में बनने वाली वस्तुओं की बिक्री केवल चीन में ही नहीं होगी।
6. अन्तर्राष्ट्रीय रिटेलर ''सस्ता खरीदो और महंगा बेचो'' के सिद्धांत पर चलती है। गहन क्षेत्रों (डीप पाकेट्स) द्वारा कम कीमत की दी गई सुविधा के कारण प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाती है और फिर कीमतें बढ़ने लगती हैं।
7. यह बात भी मिथक है कि बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे और उत्पादकों/किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बिचौलियों की समाप्ति का लाभ किसानों/उत्पादों की बजाए रिटेलरों के पास पहुंचता है। इंटरनेशनल फार्म कम्पनीज नेटवर्क (आईएफसीएन) के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा खर्च किए जाने वाले प्रत्येक डालर में से दुग्ध-उत्पादक के पास केवल 38 प्रतिशत भाग ही पहुंच पाता है। यू.के. में यह आंकड़ा 36 प्रतिशत है। भारत में, सहकारी आंदोलन के बल पर दुग्ध-उत्पादकों को उपभोक्ताओं द्वारा खर्च किए प्रत्येक रुपए का 70 प्रतिशत पहुंचता है। यदि अमरीका और यू.के. में किसान लोग रिटेलरों के कारण समृद्ध हुए हैं तो अमरीका और ईयू देशों को अपने किसानों को 400 बिलियन यूएस डालरों की प्रतिवर्ष सब्सिडी क्यों देनी पड़ती है? दैनिक रूप से इसका हिसाब

5000-6000 करोड़ रुपए बनता है।

8. एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इंटरनेशनल रिटेलरों से कोल्ड चेंज और ट्रांसपोर्ट सुविधाओं जैसे बैक-एंड आप्रेशन का लाभ मिल पाएगा, जो कि निराधार ही है। कोल्ड चेंज का निर्माण कोई रॉकेट सांइस नहीं है, मनरेगा से कोल्ड चेंज, ग्रामीण खेती, सड़कों के साथ-साथ निर्माण क्यों नहीं साथ-साथ हो सका?
9. अमरीका और ईयू देशों को बदले में पाए बिना ही उनके प्रस्तावों पर सहमत होकर व्यापारिक बातचीत के सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी गई है।
10. लोगों के बीच भी एक बात का झूठा प्रचार हो रहा है कि एफडीआई नीतियों के कार्यान्वयन पर राज्यों को विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो इसे लागू करें या न करें। ''एफडीआई'' निवेश केन्द्रीय विषय है, न कि यह राज्यों का विषय है। निवेश सम्बन्धी ऐसी किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संधि पर, जिसमें भारत एक पार्टी बनती है, उसके लिए ''राष्ट्रीय विचार विमर्श'' की आवश्यकता है। यह सरासर धोखा है जिससे पूरे देश को एफडीआई को भावी वाद-विवाद में फंसाया जा रहा है।

भाजपा ऐसे सुधारों के प्रति वचनबद्ध है जो राष्ट्रहित में हों। ''सुधारों'' का मतलब यह नहीं है कि पश्चिमी देशों के राष्ट्र जिन्हें 'सुधारों' के नाम दे देते हों, उन्हें सुधार माना जाए। पश्चिमी देशों को यह समझ लेना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में बड़े सुधारों की आवश्यकता है, वे इस प्रकार हैं:

- कृषि सब्सिडी को समाप्त करना
- आउटसोर्सिंग पर नियंत्रण हटाना
- वीसा पर अनुचित नियंत्रण समाप्त करना
- छोटे देशों की अर्थव्यवस्था के उत्पादों पर अनुचित व्यापार व्यवधान समाप्त करना।

सरकार के पास एक नहीं, अनेक घरेलू आर्थिक सुधारों का विकल्प है, जो अभी तक नहीं किए गए हैं। इन सुधारों पर व्यापक आम सहमति भी है। किन्तु सरकार है कि उसने इन सुधारों को नजरअंदाज कर रखा है परन्तु वह ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे राष्ट्रीय हितों का नुकसान होगा। ■

संशोधन

राजनीतिक प्रस्ताव

कमल संदेश (अक्टूबर 16-31, 2012) में सूरजकुंड (हरियाणा) में 26-28 सितम्बर 2012 को सम्पन्न भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं परिषद् बैठक में सर्वसम्मति से पारित 'राजनीतिक प्रस्ताव' का प्रारूप पाठ प्रकाशित हो गया था। हमें इसका खेद है। कृपया गतांक में प्रकाशित राजनीतिक प्रस्ताव में संशोधित निम्न पैरे को जोड़कर पढ़ें :

- **प्रथम पैरा निम्न प्रकार हैं-**

''भाजपा की राष्ट्रीय परिषद देश की लगातार बिगड़ती राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। आसमान छूता भ्रष्टाचार, सामाजिक-आर्थिक और सांप्रदायिक विभाजन देश में अस्थिरता के वातावरण का निर्माण कर रहा है।''

- **पृष्ठ संख्या-17 पर प्रकाशित 'आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद एवं अस्थिरता' उपशीर्षक पैरा में अंत में निम्न पंक्तियां जोड़ें-**

''पाकिस्तान, गिलगिट और बाल्तिस्तान से संबंधित प्रस्ताव और पाक-अधिकृत कश्मीर में पट्टे पर भूमि देने का विचार भी क्षेत्र में सुरक्षा के वातावरण के लिए तनाव पैदा करता है। भारत में गले तक भ्रष्टाचार ले डूबी हुई सरकार है और हमारी सुरक्षा और संप्रभुता के इन गंभीर मुद्दों पर विचार करने का समय सरकार के पास शायद ही उपलब्ध है।

आगे, सरकार भारत में ड्रग्स की बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी को नियंत्रित करने में विफल रही है। कई राज्यों में, विशेष रूप से युवा इस बुराई के शिकार हो रहे हैं। यदि इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया तो नशीली ड्रग्स की तस्करी और अवैध खुदरा बिक्री के हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह अर्थव्यवस्था में अवैध पैसे लाने के भ्रष्टाचार का दूसरा रूप है। भाजपा ''ड्रग्स खतरे'' में एक पूर्ण और व्यापक जांच की मांग करती है, जिससे भ्रष्ट नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया के बीच गठजोड़ का पर्दाफाश हो सके। शासन करने का हक खो देने से राष्ट्र का बहुत नुकसान हो रहा है।''

- **प्रस्ताव का अंतिम पैरा इस प्रकार है-**

''भाजपा की राष्ट्रीय परिषद भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान करती है कि वे सरकार में परिवर्तन लाने के लिए एक जोरदार लोकतांत्रिक संघर्ष करने के लिए तैयार रहे, जिस संघर्ष की राष्ट्र को तत्काल जरूरत है।'' ■

'सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा के रुख की पुष्टि की'

राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली द्वारा देश के प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति पर प्रस्तुत विचार

गत 12 अप्रैल 2012 को परामर्श प्रदान करने के अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था के अन्तर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने के लिए एक राष्ट्रपति संदर्भ भेजा गया। यह संदर्भ 2008 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 122 स्पेक्ट्रम 2जी लाइसेंसों को रद्द किए जाने के बाद भेजा गया।

इस संदर्भ के माध्यम से 8 प्रश्नों का एक सैट था, जिसके उत्तर/विचार मांगे गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्नों के प्रथम 5 सैटों का उत्तर प्रस्तुत किया है। शेष प्रश्नों पर उसने इस आधार पर उत्तर नहीं दिया है कि ऐसा करने से स्वयं स्पेक्ट्रम आवंटन प्रभावित हो सकता है।

न्यायालय का विचार है कि "इस संदर्भ का प्रयोजन तभी पूर्णतः सिद्ध हो सकेगा, यदि- आर्थिक उत्तर की अपेक्षा न्यायालय संवैधानिक उत्तर दे।"

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का निपटान करने की विधि एकदम आर्थिक नीति से जुड़ी है। न्यायालय सभी तथ्यों और परिस्थितियों में एक ही प्रकार की विधि अपनाने का निर्देश नहीं दे सकता है। किन्तु, न्यायालय इन विधियों की वैधता और संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है। प्रश्नचिह्न लगाए जाने पर न्यायालय उनका विश्लेषण करेगा और उन विधियों के संविधान प्रावधानों के शक्ति-बाह्य होने-न होने पर संवैधानिक निर्णय देगा।

और, यदि कोई नीति इस हद तक स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण नजर आती है जिससे वह संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों की निष्पक्षता की नीयत पर खराब उतरती है तो उस नीति को निरस्त करने में न्यायालय संकोच नहीं करेगा।

प्रमुख बिंदुओं की प्रस्तुति-

1. **प्राकृतिक संसाधनों की विलगता** = नीति निर्णय के लिए अपनाए गए साधन = सरकार का विशेषाधिकार
2. जब दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को निजी उद्यमों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापारिक कार्यों के लिए अलग किया जाता है, जिनमें प्रतिस्पर्धी और अधिकतम राजस्व के अलावा अन्य साधनों को अपनाया जाता है तो ये मनमाने अर्थात् अर्बिट्रेरी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये नीतियां संविधान के अनुच्छेद 14 पर खरी नहीं उतर सकती है।
3. किन्तु, जब बात सामाजिक या कल्याणकारी प्रयोजनों पर नीति-निर्णय की होती है तो नीलामी/प्रतिस्पर्धी बोली और अधिकतम राजस्व के अलावा अन्य विधियों को अपनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी, वस्तुपरक कसौटी को सामने रखना जरूरी होगा और उसके कारण को रिकार्ड करना आवश्यक होगा।
4. अतः, सर्वोच्च न्यायालय ने इन आधारों पर प्राकृतिक संसाधनों के निपटान पर किसी एक विधि को अपनाने या उसका निषेध करने से गुरेज किया है।
5. प्रत्येक मामला तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। यह मामला सामाजिक और कल्याणकारी प्रयोजनों पर अथवा निजी उद्यमों के माध्यम से वाणिज्यिक कार्यों के प्रयोजनों से जुड़े अधिकतम राजस्व की प्राप्ति के सिद्धांतों पर हो सकता है।
6. जब दुर्लभ संसाधनों के वाणिज्यिक प्रयोग के प्रयोजन से इन संसाधनों को विलग कर अधिकतम राजस्व प्राप्त करने की बात आती हो तो सरकार के ऐसे किसी काम को अनुच्छेद 14 की भावना के खिलाफ मनमाना, अनौचित्यपूर्ण और हास्यास्पद माना जा सकता है।

श्री अरुण जेटली का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो विचार अभिव्यक्त किए हैं, उनसे कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब प्राइवेट आप्रेटरों को वाणिज्यिक प्रयोजनों से आवंटन किया गया हो तो इससे अधिकतम राजस्व के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी गई क्योंकि आवंटन के लिए जिस विधि को अपनाया गया उसमें प्रतिस्पर्धी बोली को नहीं अपनाया गया।

यही वह आधार रहा है जिसके कारण भाजपा ने कोल आवंटनों को रद्द करने की मांग की है। ■

'यूपीए शासन में एक घोटाला सामने आता है तो दूसरा घोटाला खड़ा हो जाता है'

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा आर्थिक प्रस्ताव पर प्रस्तुत कुछ बिन्दु

इससे पूर्व कि मैं अन्य मुद्दों पर चर्चा करूं, मैं रिटेल में एफडीआई पर श्री अरुण जेटली के विचारों में कुछ और जोड़ना चाहूंगा।

कांग्रेस अध्यक्षा का कहना है कि भाजपा विपक्ष के रूप में नकारात्मक भूमिका निभा रही है। कांग्रेस पार्टी को तो गठबंधन की कला मालूम ही नहीं है। कांग्रेस दोहरे मानदण्ड अपनाती है और अपने ही सहयोगी दलों को विश्वास में नहीं लेती है। वह संसद में वचन देती है और फिर देश को धोखा देती है।

कांग्रेस ने सुधारों का विरोध किया, विशेष रूप से रिटेल में एफडीआई का। हम सभी जानते हैं कि श्री प्रिय रंजन दासमुंशी ने इसे 'राष्ट्र-विरोधी' कहा था। वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी, जब वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते थे तो उन्होंने भी रिटेल में एफडीआई का विरोध किया था। हमारे पास उनकी इस बात के प्रमाण हैं। उस समय उन्होंने जो कहा था, वह यह था कि ''भारत को ऐसी किन्हीं सुधारों की आवश्यकता नहीं है, जिनसे रोजगार पैदा होने की बजाए, रोजगार ही खत्म हो जाएं।'' उनकी यह प्रतिक्रिया फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के प्रत्यावेदन के जवाब में कही गई थी। उन्होंने फेडरेशन को अपने 21 दिसम्बर 2002 के पत्र के माध्यम से यह भी बताया था कि रिटेल ट्रेड में एफडीआई सम्बन्धी मामला राज्यसभा में उठाया गया था और वित्त

मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार के पास रिटेल ट्रेड में एफडीआई लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब, आप ही बताइए कि दोहरे मानदण्ड कौन अपना रहा है? कांग्रेस या भाजपा?

प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि देश में ''1991 जैसे हालात पैदा होते जा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप और आपकी पार्टी पिछले आठ वर्षों से सत्ता में है। जब हमने 2004 में आपको सत्ता सौंपी थी तो आपको 2004 में संसद में प्रस्तुत आपके अपने ही आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार एक भरी-पूरी अर्थव्यवस्था मिली थी। इसमें आरम्भ के वाक्य ही की शुरूआत इस बात से हुई थी- ''विकास, मुद्रास्फीति और भुगतान संतुलन के रूप में अर्थव्यवस्था नई ऊर्जा का संचार दिखाई पड़ता है, जो हमारे सामने एक ऐसी संघटित स्थिति पेश करता है जिससे विकास की तीव्र गति के साथ साथ मैक्रो-इकॉनामिक स्थिरता के एकीकरण की भारी गुंजाइश दिखाई पड़ती है।'' 8 जुलाई 2004 को बजट पेश करते हुए आपके वित्त मंत्री ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को स्वीकार किया था और कहा था- ''लगता है कि आर्थिक मूल-सिद्धांत पूरी तरह दृढ़ हैं और भुगतान-संतुलन पूरी तरह स्वस्थ है।'' आपने सफलतापूर्वक शासन किया और पिछले आठ वर्षों में अपनी गलत प्राथमिकताओं, नीतिगत पंगुता और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था को तबाह कर डाला।

इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता हमें बढ़ती कीमतों के मोर्चे पर देखने को मिलती है। हर चीज़ की कीमत, चाहे वह मटर, दाल, कोयला, तेल, चीनी, चावल, गेहूं- कुछ भी हो, हर चीज; आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। आपने ईंधन की कीमतों में 24 गुणा वृद्धि कर डाली। आपने 24 महीने में ही फर्टिलाइजर की कीमतों को 12 गुना बढ़ा दिया। इसी प्रकार उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, बीज, ट्रेक्टर भाड़ा की कीमतों सभी में बेहद इजाफा हुआ और जिससे किसानों को आत्महत्या करने

पर विवश होना पड़ा। किसान रो रहे हैं और आपकी सरकार सो रही है। उर्वरकों के मामले में डीएपी कीमतें 111 प्रतिशत से बढ़कर 170 प्रतिशत हो गईं अर्थात् 517.40 रुपए से बढ़ कर 1315 रुपए हो गईं। कम्पलेक्स फर्टिलाइजर्स की कीमतें 176 प्रतिशत से बढ़कर 205 प्रतिशत हो गईं अर्थात् 472 से बढ़ी तो 1298 तक पहुंची। एमओपी कीमतों की बढ़ोतरी 156 प्रतिशत से 282 प्रतिशत हो गईं। ट्रेक्टर किराया भाड़ा, जो 2010 में 800 रुपए था, वह अब 2500 रुपए तक जा पहुंचा।

आपने डीजल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। यह एक ऐसी बात है जो हमने स्वतंत्रता के बाद आज तक कभी नहीं देखी। आपका कहना है कि डीजल का उपयोग तो केवल अमीर लोग करते हैं। तो क्या आपके कहने का मतलब यह है कि जितने किसान हैं, वे सभी अमीर हैं? यात्री ले जाने वाले वाहन भी डीजल का उपयोग करते हैं। ट्रेक्टर भी डीजल से चलते हैं। गरीब किसानों के पम्प सैटों को भी डीजल की जरूरत होती है। इससे कृषि पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। किसान तो पहले ही मरा पड़ा है, वह तो पूरी तरह से लाचार हो जाएगा। उनके फसल बोने की लागत और भी अधिक बढ़ जाएगी और इसे बड़े पैमाने पर उनका गांवों से भागना शुरू हो जाएगा। परिवहन की लागत भी बढ़ जाएगी। ट्रेक्टर किराया भाड़े में भी और अधिक वृद्धि हो जाएगी। आज तो हम देख रहे हैं कि पहले ही प्रत्येक राज्य सरकार ने स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन बसों के यात्रा किराए बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। यह सारा बोझ 40,000 करोड़ रुपयों से अधिक का हो जाएगा। सड़क परिवहन की लागत भी बढ़ेगी। आल इण्डिया मोटर कांग्रेस ने पहले ही 15 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा कर दी है, न जाने, यह किस प्रकार के सुधार हैं? पहले कुछ करके दिखाओ और फिर सुधार करो।

आपने एलपीजी सिलेण्डरों पर अंकुश लगा दिया है और कहा है कि 50 प्रतिशत से अधिक लोग वर्ष में केवल छः सिलेण्डरों का इस्तेमाल करते हैं। वाह, कितना बड़ा ब्यौरा आपने दे डाला है? एक औसत गरीब परिवार को वर्ष में 12 से 15 सिलेण्डरों की जरूरत होती है। यदि आपका कहना सही है तो कांग्रेस अध्यक्षा ने वर्ष में 9 सिलेण्डर देने की बात क्यों कही है? आपकी आपनी अध्यक्षा ही आपकी बात काट रही है।

एनडीए शासन की तुलना यूपीए शासन से कीजिए। हमारे शासन काल में कीमतें नियंत्रण में थी- कहीं कोई लाइन नहीं, कोई कतार नहीं, कोई प्रतीक्षा-सूची नहीं, कोई कमी नहीं, कोई काला बाजारी नहीं। कनेक्टिविटी क्रांति ने जन्म लिया जिसमें रेल कनेक्टिविटी, हाइवे-कनेक्टिविटी, ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी, पोर्ट और एयर कनेक्टिविटी शामिल हैं। इसी प्रकार टेलीकॉम क्रांति

शेष पृष्ठ 25 पर

M.R.P. PRICES OF FERTILIZERS YEAR-WISE FROM 2010 – 2012
(For a 50 kg bag - In Rupees)

Product	17.06.2008 to 31.03.2010	01.04.2010 to 31.12.2010	01.01.2011 to 31.03.2011	April 2011	July 2011	Sept 2011	Oct 2011	Nov 2011	Jan 2012	Feb/Mar 2012	Apl/May 2012	Jun 2012	Jul/Aug 2012
D.A.P.	486.2	517.4	559	624.00	635.00	800.00	953.00	955.50	1014.00	924.00 to 1014	955.00 to 1023.75	1087.00 to 1260.00	1023.75 to 1315.00
M.O.P.	231.66	262.86	262.86	312.00	315.00	442.00	594.00	594.00	594.00	592.00 to 630.00	588.00 to 834.80	592.55 to 885.00	592.55 to 885.00
Complex	266.00 to 425.00	309.00 to 480.61	469.00 to 581.41	430.00 to 615.00	560.00 to 715.00	624.00 to 728.00	636.75 to 981.75	636.75 to 981.75	609.97 to 981.75	-	689.53 to 1113.00	735.00 to 1297.80	735.00 to 1297.80
Urea	250.08	275.76	275.76	281.10	281.10	281.10	281.10	281.10	281.10	281.10	281.10	281.10	281.10

- Prices of Fertilizers have increased 12 times in 24 months
    - DAP prices have gone up by 111% to 170%
- *For example, DAP price gone up from 517.40 to 1315.*
    - Complex fertilizers have gone up by 176% to 205%
- *For example, prices rose from 472 to 1298.*
    - MOP prices have risen by 156% to 282%.
- Tractor hiring charges in 2010 was Rs.800/- per acre. Today it is Rs.2500/-
    - Diesel prices too have gone up during the period.

वीबीएस का रहस्य

✍ अरुण जेटली

मीडिया में आई खबरों से यह तथ्य सामने आया है कि एक स्टील निर्माता कंपनी पर आयकर विभाग ने छापा मारा था और उसके द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों और व्यक्तियों को किये गए भुगतान की जानकारी मिली थी। भुगतान वर्ष 2007 से 2010 के दौरान किये गए। स्टील मंत्रालय के कर्मचारियों को बड़ी संख्या में भुगतान किये गए। स्टील मंत्रालय से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों और सरकार में कुछ प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्तियों पर भी भारी राशि खर्च की गई। एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक में आई खबर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है जिसका शीर्षक है, ''एमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस सीबीआई, ईडी।'' वर्ष 2009-10 के दौरान 'वीबीएस' के रूप में चर्चित एक कंपनी को किये गए पांच विभिन्न भुगतानों का विवरण दिया गया है। यह वीबीएस कौन है? क्या यह राजनीतिक भुगतान है।

तत्कालीन इस्पात मंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने खंडन किया है कि 'वीबीएस' का उनसे कोई संबंध है। उनका कहना है कि वे अपना संक्षिप्त नाम 'वीएस' लिखते हैं 'वीबीएस' नहीं। उन्होंने इस बारे में अनभिज्ञता दिखाई है और आरोप लगाया है कि इस खुलासे में बीजेपी का हाथ है।

श्री वीरभद्र सिंह हर तरह से गलत हैं। मामला यह नहीं है कि वह अपना संक्षिप्त नाम 'वीएस' या 'वीबीएस' लिखते हैं। मामला यह है कि क्या इस्पात निर्माता जिसने इन बहीखातों को रखा है, उसमें उनका संक्षिप्त नाम 'वीबीएस' है या नहीं।

निश्चित तौर पर भाजपा या उसके किसी अन्य सदस्य ने इन बहीखातों को तैयार नहीं किया है। आयकर विभाग ने कंपनी पर छापा मारा। ये दस्तावेज आयकर विभाग के पास दिसम्बर 2010 से हैं। केवल वही उन्हें लीक कर सकते थे। भाजपा इस पूरे लेन-देन में अजनबी है।

श्री वीरभद्र सिंह हर तरह से गलत हैं। मामला यह नहीं है कि वह अपना संक्षिप्त नाम 'वीएस' या 'वीबीएस' लिखते हैं। मामला यह है कि क्या इस्पात निर्माता जिसने इन बहीखातों को रखा है, उसमें उनका संक्षिप्त नाम 'वीबीएस' है या नहीं।

बहीखाते 'वीबीएस' के खिलाफ प्रतिग्राह्य सबूत हैं

कांग्रेस पार्टी कथित रुप से 'वीबीएस' के बचाव में यह कहते हुए कूद गई है कि एक डायरी कोई प्रतिग्राह्य सबूत नहीं है। उन्होंने बदनाम जैन हवाला मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उदाहरण दिया है। जैन हवाला फैसले का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए मेरे पास यह कारण हैं-

बहीखाते 'वीबीएस' के खिलाफ प्रतिग्राह्य सबूत हैं

कांग्रेस पार्टी कथित रुप से 'वीबीएस' के बचाव में यह कहते हुए कूद गई है कि एक डायरी कोई प्रतिग्राह्य सबूत नहीं है। उन्होंने बदनाम जैन हवाला मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उदाहरण दिया है। जैन हवाला फैसले का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए मेरे पास यह कारण हैं-

- ये नियमित बहीखाते हैं। इनमें क्रम संख्या, भुगतान या प्राप्ति की तारीख, जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया, जिस व्यक्ति ने कथित भुगतान को अधिकृत किया, कितनी धनराशि का भुगतान किया गया या प्राप्त की गई और खाते में कितनी धनराशि बची, उसकी जानकारी है। यह बताने की जरुरत नहीं कि पूरा भुगतान नगद में किया गया। खाते का 'सीएमडी खाता' के रुप में जिक्र है।
- ये नियमित बहीखाते हैं जो सामान्य तौर पर व्यापार के लिए रखे जाते हैं और सम्बद्ध सबूत हैं। (साक्ष्य अधिनियम का अनुच्छेद 34)
- इनकी सत्यता पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आयकर छापे के दौरान बरामद हुए हैं।
- ये बहीखाते लिखित में स्वीकृति हैं जो स्वीकृति देने वाले के खिलाफ स्वीकार करने योग्य हैं यानि स्टील कंपनी इस्पात (साक्ष्य अधिनियम के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21)
- इन बहीखातों से रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले के बीच आपराधिक साजिश की झलक

मिलती है।

साक्ष्य का अनुच्छेद 10 इस स्थिति से संबद्ध है। जैन हवाला मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला इस सिद्धांत को अनुमोदित करता है कि – (क) कोई अपराध करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों ने साजिश की है (ख) कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनमें से किसी के द्वारा कहा गया हो या लिखा गया हो और (ग) यह सभी की मंशा के बारे में है।

अगर ये सभी हालात किसी साजिशकर्ता द्वारा की गई स्वीकृति को संतुष्ट करते हैं तो यह एक अन्य सह साजिशकर्ता के खिलाफ स्वीकार करने योग्य सबूत हैं। वास्तव में लिखित में स्वीकृति की गई है। एक वर्ष के दौरान जब पांच भुगतान किये गए, रिश्वत का कार्य किया गया, इसकी प्रविष्टि बहीखातों में हुई और साजिश (खातों में प्रविष्टि) के निष्पादन के दौरान स्वीकृति की गई। अनुच्छेद 10 की व्यावहारिकता को जैन हवाला मामले में नामंजूर किया गया क्योंकि लिखित में स्वीकृति साजिश के बाद की गई जिसमें अनुच्छेद 10 लागू नहीं होता। यहां स्थिति अलग है। स्वीकृति करीब एक वर्ष तक साजिश की अवधि के दौरान की गई।

- केवल इस बात की जांच करना बाकी है कि क्या ऐसा कोई प्रमाण है जिससे इन डायरियों की जानकारियों की पुष्टि होती हो। यह जांच का विषय होगा। जांच में जांचकर्ता को उस व्यक्ति का पता लगाना होगा जिसने भुगतानों को अधिकृत किया। इस मामले में 'वीबीएस' को किये गए अधिकतर भुगतानों को 'एकेएस' ने अधिकृत किया। किसी अनुभवी जांचकर्ता के लिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि 'एकेएस' कौन है। एकेएस और वीबीएस के बीच संपर्क की जांच करना जरुरी है। स्टील कंपनी से जुड़े किसी भी मामले से निपट रही वीबीएस की जांच करना जरुरी है। इस तरह की जांच कोई कठिन नहीं है।
- भ्रष्टाचार निरोधक कानून का उपयोग करने के लिए किसी प्रतिदान की जरुरत नहीं है। कानून का अनुच्छेद 20 स्पष्ट तौर पर कहता है कि जब कोई सरकारी अधिकारी कानूनी तौर पर जायज भुगतान के अलावा कोई धनराशि लेता है तो यह गैरकानूनी संतुष्टि का अनुमान है।

सच्चाई को छिपाना मुश्किल है क्योंकि यह खुद ही बाहर आ जाती है। प्रधानमंत्री अब क्या करने जा रहे हैं। क्या वह नकारात्मकता के माहौल की बात करके तथ्यों की अनदेखी कर देंगे? क्या उन्हें और कांग्रेस अध्यक्ष को इन तथ्यों की जानकारी थी जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक बदलाव के संबंध में कुछ फैसले किये?

क्या सीबीआई इस मामले की जांच कर सकती है?

जाहिर है कि सीबीआई इस मामले की जांच नहीं कर सकती। इन डायरियों में कार्पोरेट ग्रुप द्वारा सीबीआई और ईडी पर खर्च की गई राशि की जानकारी है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें कानूनी प्रक्रिया शुरु की जानी चाहिए और इसे एसआईटी टीम को दे देना चाहिए जिसमें निर्विवाद ईमानदार अधिकारी हों।

वीबीएस की पहचान

अगर इस्पात मंत्रालय और उनके पीएसयू के अधिकारियों को सीएमडी खाते के अंतर्गत भुगतान किये गए, तो किसी भी जांचकर्ता के लिए 'वीबीएस' का अर्थ निकालकर उसकी पहचान करना मुश्किल नहीं है। साक्ष्य अधिनियम के अनुच्छेद 114 तथ्य के होने का अनुमान लगाने की इजाजत देता है जिसमें लगता है कि सार्वजनिक और निजी व्यवसाय में ऐसा हुआ होगा।

राजनीतिक मुद्दा

ये खाते पिछले 22 महीनों से आयकर अधिकारियों के कब्जे में हैं। निश्चित तौर पर सीबीडीटी, राजस्व सचिव और वित्त मंत्रालय को इसकी जानकारी रही होगी। क्या यह मामला वित्त मंत्री की जानकारी में लाया गया? यह साफ है कि यह केवल राजस्व से जुड़ा मामला नहीं है। इसके भारत की शासन व्यवस्था पर गंभीर परिणाम होंगे। यह भ्रष्टाचार का मामला है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उचित भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र के ध्यान में यह मामला क्यों नहीं लाया गया और विभिन्न जांच प्रक्रियाएं शुरु क्यों नहीं की गई। कोई भी सरकारी अधिकारी जिसने एक अपराध को मान्यता दी है, खुद भी कर्तव्य में लापरवाही बरतने का अपराधी है। यह साफ है कि सरकार इस तथ्य को छिपाना चाहती है। सच्चाई को छिपाना मुश्किल है क्योंकि यह खुद ही बाहर आ जाती है। प्रधानमंत्री अब क्या करने जा रहे हैं। क्या वह नकारात्मकता के माहौल की बात करके तथ्यों की अनदेखी कर देंगे? क्या उन्हें और कांग्रेस अध्यक्ष को इन तथ्यों की जानकारी थी जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक बदलाव के संबंध में कुछ फैसले किये? उनकी चुप्पी भ्रष्टाचार के प्रति उनके समर्थन को दर्शाएगी। ■

(लेखक राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं)

आर्थिक सुधार या बंटाधार

&,l- x#efrl

तारीख, 14 सितंबर 2012, दिन शुक्रवार, भारत में जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमरीकी कम्पनी वॉलमार्ट के लिए रेड कार्पेट बिछाया, तो अपने ही देश के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शुक्रवार के दिन ही यूपीए सरकार ने एफडीआई के लिए वॉलमार्ट से हाथ मिलाया और लॉबिस्टों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि छोटे व्यवसायी सुरक्षित हैं। एक विदेशी मामलों की बहुचर्चित पत्रिका के वेब पोर्टल ने हृदय विदारक हैडिंग लगाई, 'मौत का आनंद – कैसे वॉलमार्ट छोटे व्यवसायियों को विस्थापित कर रहा है'। कुछ सप्ताह पहले लॉस एंजिल्स की सड़कों पर 10 हजार लोग, जो भारत में लाखों लोगों के बराबर हैं, चिल्ला रहे थे कि वॉलमार्ट का मतलब है, गरीबी। एक जून को सैकड़ों लोगों ने वॉशिंगटन में वॉलमार्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया।

वॉलमार्ट को ना कहने वाला आंदोलन पूरे अमरीका में जोरों पर है, लेकिन सवाल है कि हम वॉलमार्ट पर ही ध्यान क्यों केंद्रित करें? वॉलमार्ट विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली खुदरा व्यापार कम्पनी है। इसने यूपीए सरकार को रिटेल में एफडीआई के पक्ष में करने के लिए अत्यधिक धन खर्च किया है। हालांकि, जब लॉबिस्ट यहां वॉलमार्ट के आने का उत्सव मना रहे हैं, तो यह उस अमरीका में बेकार हो गया है, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन अमरीका में वॉलमार्ट को घृणा की दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है? न्यूयॉर्क के व्यापारिक संगठन और स्थानीय समुदाय कह रहे हैं कि वॉलमार्ट स्थानीय व्यापार को चौपट कर देगा।

जब यूएस के किसान वॉलमार्ट से अच्छे दाम हासिल कर रहे हैं, तो फिर क्यों यूएस सरकार अपने किसानों के लिए सालाना 20 अरब डॉलर की सब्सिडी जारी करती है? यूएस और पश्चिमी देशों के अनुभव के आधार पर यूपीए की एफडीआई के पक्ष में दलील पर सवालिया निशान लगाया जा सकता है। रिटेल में एफडीआई से भारत में 120 लाख रिटेलर परिवारों को नुकसान होगा। यह किसानों को फायदा तो दूर, नौकरियों में और कटौती करेगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे करीब दो तिहाई ग्रामीण भारतीयों की खाद्य सुरक्षा मिट जाएगी। आखिर कैसे सुधारों का दावा करने वाले लोग बगैर जमीनी असलियत जानें, एफडीआई से बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं?

लॉस एंजिल्स में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों का भी कहना था कि छोटे खुदरा व्यापार बंद हो जाएंगे और वो चीख-चीख कर कहते हैं कि वॉलमार्ट के पास न तो दिल है और न ही उसमें कोई नैतिकता है, लेकिन अमरीकी राजनीतिज्ञ भी यूपीए सरकार की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पिछले मार्च में लॉस एंजिल्स सिटी काउंसिल ने बड़े खुदरा उपक्रमों की स्थापना पर रोक लगा दी थी, लेकिन वॉलमार्ट को भवन बनाने का आदेश एक दिन पहले जारी कर दिया गया। लॉस एंजिल्स टाइम्स अखबार ने भी वॉलमार्ट के खिलाफ लिखा।

अभी भी यूपीए सरकार कह रही है कि वॉलमार्ट और इसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियां छोटे खुदरा व्यापारियों और किसानों के साथ सहृदयता बरतेंगी। सरकार यह गारंटी देती है कि वॉलमार्ट यहां लाखों नौकरियां लाएगा। लेकिन अमरीकी साक्ष्य इससे उलटी हकीकत बयान करते हैं। अटलांटिक सिटी के मुताबिक वॉलमार्ट ने शिकागो के ऑस्टिन नेबरहुड में वर्ष 2006 में प्रवेश किया और वर्ष 2008 तक 306 छोटी दुकानों में से 80 दुकानें बंद हो गई। नौकरियों के सृजन के मामले में एक हालिया रिपोर्ट (जनवरी 2010) का शीर्षक है, 'वॉलमार्ट का आर्थिक फुटप्रिंट', जिसे न्यूयॉर्कसिटी के पब्लिक एडवोकेट के लिए तैयार किया गया है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक वॉलमार्ट की दो नौकरियां पैदा होने से तीन

स्थानीय नौकरियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए नौकरियों के सृजन का तर्क बेबुनियाद है। तीसरा तर्क कि किसानों को अच्छी कीमतें मिलेंगी। यह एक कुटिल चाल है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। यह उस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपा रहा है कि वॉलमार्ट काउंटर पर न तो कुछ खरीदता है और न ही वहां पर भुगतान करता है।

यह देश में भविष्य में होने वाली अगली फसल को बाजार से खरीदता है और वहां से पूर्व निर्धारित कीमतों पर सामान खरीदता है। यह चीन से सस्ते सामानों का आयात करता है और स्थानीय उत्पादों को नष्ट कर देता है, जैसा कि इसने अमरीका में किया है। अमरीका और विश्व के हालिया अनुभव से पहला उदाहरण लेते हैं। जनवरी 2007 की तुलना में अप्रेल 2008 में चावल की कीमतें अमरीका सहित पूरे विश्व में तीन गुनी ज्यादा हो गई। उस समय के तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक हास्यास्पद बयान दिया था कि कीमतों में वृद्धि इसलिए हुई है, क्योंकि भारत का नवधनाढ्य वर्ग ज्यादा खाना खाता है। लेकिन सच क्या था? यूएसए टुडे (23.04.08) और सीएनएन (24.04.08) के मुताबिक कैलिफॉर्निया चावल आयोग और यूएस चावल संघ ने चावल की कमी होने से इंकार किया और कहा कि चावल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद था। तो फिर चावल के दाम क्यों बढ़ रहे थे? सीएनएन के मुताबिक सैम्स क्लब (वॉलमार्ट का थोक विक्रय विभाग) भारी मात्रा में स्टॉक्स को दबाये बैठा था, जिससे दाम बढ़ते जा रहे थे।

यूएस के किसानों ने कीमतों में उछाल के लिए सट्टेबाजों और वायदा बाजार को दोषी ठहराया। किसानों ने बेचान तो किया, लेकिन वायदा कारोबार नहीं हुआ।

जनवरी 2008 में गेहूं के वायदा कारोबार में निवेश फंड्स की जो हिस्सेदारी 40 फीसद थी, वह अप्रेल तक 60 फीसद हो गई। 2007 के पूर्व में गेहूं का वायदा सौदा जो चार डॉलर बुशेल था, वह अप्रैल 2008 तक 14 डॉलर प्रति बुशेल हो गया। यूएस के जिस किसान ने अपनी पैदावार वायदा बाजार में बेची, उसे भारी नुकसान हुआ और वॉलमार्ट उतने ही मुनाफे में रहा। जब कुछ किसान अपने बचे हुए स्टॉक्स बेचना चाहते थे, तो वॉलमार्ट ने ऊंची कीमतों पर खरीदने से इंकार कर दिया।

यह स्थिति सब कुछ बयां करती है। जब यूएस के किसान वॉलमार्ट से अच्छे दाम हासिल कर रहे हैं, तो फिर क्यों यूएस सरकार अपने किसानों के लिए सालाना 20 अरब डॉलर की सब्सिडी जारी करती है? यूएस और पश्चिमी देशों के अनुभव के आधार पर यूपीए की एफडीआई के पक्ष में दलील पर सवालिया निशान लगाया जा सकता है। रिटेल में एफडीआई से भारत में 120 लाख रिटेलर परिवारों को नुकसान होगा। यह किसानों को फायदा तो दूर, नौकरियों में और कटौती करेगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे करीब दो तिहाई ग्रामीण भारतीयों की खाद्य सुरक्षा मिट जाएगी। आखिर कैसे सुधारों का दावा करने वाले लोग बगैर जमीनी असलियत जानें, एफडीआई से बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं? ■

(राजस्थान पत्रिका से साभार)

पृष्ठ 11 का शेष...

फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। हम एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिससे इन लोगों को बराबर के अवसर प्रदान हो, उनके अधिकार सुरक्षित हो और वे समाज में पूरे भागीदार बने, जिसमें शिक्षा और रोजगार दोनों ही शामिल है। भारत पहला ऐसा देश रहा है जिसने 2007 में 'कंवेंशन आन दि राइट ऑफ पर्सनस विद डिसऐबिलिटी' पर हस्ताक्षर किए थे और इसे स्वीकार किया था।

हमारे देश में 60 वर्ष की आयु के लगभग 100 मिलियन लोग हैं। हमारा मानना है कि हमारे ये बुजुर्ग लोग सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने कार्यस्थल और समुदाय के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। हमने ऐसे कई उपाए किए हैं, जिनमें कानून बनाना भी शामिल है, जिनसे ये बुजुर्ग प्रतिष्ठा का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन उपायों में परिवार द्वारा की गई स्वास्थ्य देखभाल, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, वृद्ध आश्रमों की स्थापना, जरा-चिकित्सा सुविधा में शोध तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहन तथा कानूनी सेवाओं सहित सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।

हम विश्व समुदाय के प्रयासों को भी मजबूत करने को महत्वपूर्ण मानते हैं ताकि 2002 मैडरिड प्लान ऑफ एक्शन तथा अन्य जुड़े मुद्दों के कार्यान्वयन में अंतरों का समाधान किया जा सके।

मि. चेयरमैन,

स्थायी, सद्भावपूर्ण, शांतिप्रिय और न्यायोचित समाज के निर्माण तथा सभी लोगों के उत्कृष्ट जीवन में व्यापक सुधार लाने के लिए व्यापक एवं समावेशी सामाजिक विकास अत्यंत आवश्यक है। इस महत्वाकांक्षा को वास्तविकता में परिणित करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए हम अपनी वचबद्धता को दोहराने के लिए कृतसंकल्प हैं। ■

'शिवाजी और सुराज' सुशासन का ब्लूप्रिंट

✍ विकास आनन्द

15 अगस्त 1947 की आधी रात में हमने अंग्रेजों से एक लम्बी लड़ाई के बाद स्वराज तो पा लिया लेकिन अभी तक हम सुराज की अवधारणा को मूर्त रूप देने में असमर्थ रहे हैं। आज हमारे देश में एक विचित्र वातावरण बना हुआ है। नित्य नये घोटाले उजागर हो रहे हैं। कुशासन के रोज नये उदाहरण समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रहे हैं। कहीं न कहीं इसके लिए हमारे राजनेता (शासक) दोषी हैं। उनमें कुछ कमियां रही हैं। जो सुराज पाने में अभी तक रूकावट बनी हुई है। भारत के इतिहास में ऐसे कई शासक हुए हैं जिनकी शासन कला या राज्य नीति से आज के शासक बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन्हीं महान शासकों में एक थे शिवाजी। शिवाजी ने अपनी कुशल शासन नीति द्वारा अपने स्वराज को सुराज में परिवर्तित किया था।

अभी हाल ही में शिवाजी के शासन कला पर आधारित पुस्तक 'शिवाजी और सुराज' प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के लेखक हैं अनिल माधव दवे। यह पुस्तक गहन शोध पर आधारित है। 'शिवाजी और सुराज' में लेखक ने शिवाजी के शासन व्यवस्था का ही जिक्र नहीं किया है बल्कि उदाहरणों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि किस तरह शिवाजी की शासन कला आज के शासकों के लिए भी प्रासंगिक है।

लेखक बताते हैं कि शिवाजी स्वराज के कल्पना का संप्रेषण सफलतापूर्वक इसलिए कर पाये क्योंकि शिवाजी ने कभी नहीं कहा और न ही कहलवाया कि 'स्वराज मेरी अवधारणा' है। उन्होंने हमेशा स्पष्ट शब्दों में कहा 'स्वराज यह श्री की इच्छा है'।

लेखक का कहना है कि आज देश में दृश्य ठीक विपरीत है। सरकार हो या संगठनों के नेता, वे हर योजना को 'मेरी योजना' कहकर संबोधित करते हैं। लेखक का कहना है कि यही कारण है व्यक्ति विशेष के पद से हटते हैं। उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं सामान्यत: हवा हो जाती हैं। लेखक स्वतंत्र भारत में 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' को अधिक सफल लाभकारी और स्वीकार्य बताते हैं। इसकी सफलता का मूलमंत्र इसके नाम में छिपा है। यह 'अटल ग्राम सड़क योजना' के नाम से भी चलाई जा सकती थी। लेकिन लेखक कहते हैं कि सफल नायक ऐसा नहीं करते। कार्य व्यक्ति प्रारंभ करता है किंतु उसका विकास व विस्तार दल/टीम करती है। सामान्यत: नायक टीम चयन में अपनी जाति, जमात या जी-हजूरी वालों को प्राथमिकता देता है। इस कारण कार्य की हानि होती है।

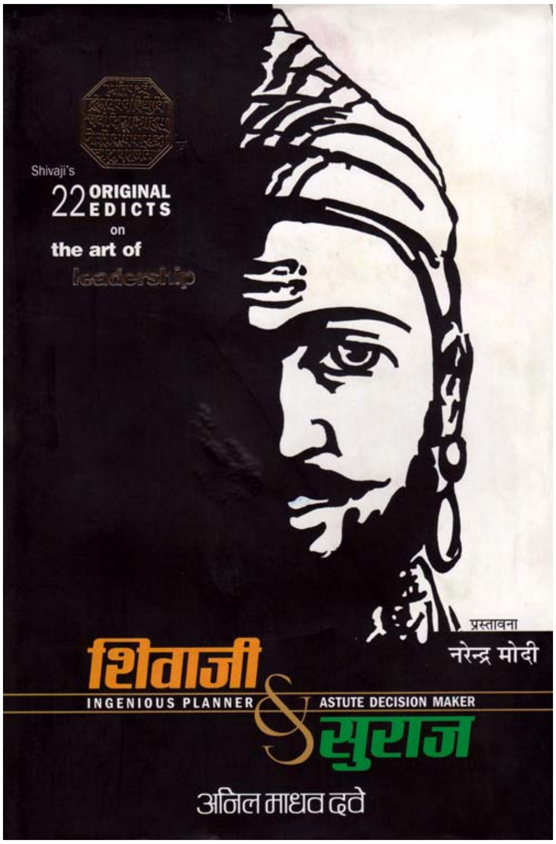

लेखक : अनिल माधव दवे
प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य : रु 500
संस्करण : प्रथम 2012
पृष्ठ सं. : 231 + xxxii

यह पुस्तक बताती है कि किसी भी राज्य या संगठन, परिवार के छोटे-बड़े निर्णय करना हो, सभी का आधार आस्था है, जो विश्वास की भूमि पर जन्म लेता है। नेतृत्व करने वाले नायक में सहकर्मियों की आस्था या शासक में जनता की आस्था जरूरी है। आस्था होना सफल शासक के लिए आवश्यक

है। इसी आस्था की बदौलत शिवाजी की पंद्रह-बीस हजार की सेना अफजल खां की तीस-पैंतीस हजार की सेना को हरा दिया था।

में किए गए आकलन को शिवाजी त्रुटिशून्य रखते थे। शिवाजी की आकलन व मूल्यांकन की क्षमता शासकों के लिए अनुकरणीय है।

शिवाजी भ्रष्टाचार के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, इस सम्बंध में इस पुस्तक में एक घटना का जिक्र किया गया है कि शिवाजी के मामा मोहित ने रिश्वत ली, यह जानकारी शिवाजी महाराज को मिली तो उन्होंने उसे तत्काल कारागार में डाल दिया और छूटने पर पिता शाहजी के पास भेज दिया। यह पुस्तक उनके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगी जो शासन-सत्ता में किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं। चाहे वह नौकरशाह हो या राजनेता।

आज देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि मैं सहयोगी दलों के असहयोग के कारण कोई निर्णय नहीं ले पाता हूं। इसका मतलब साफ है मनमोहन सिंह में उनके सहयोगी दलों का विश्वास नहीं है।

इस प्रकार लेखक ने उदाहरण के साथ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि शिवाजी और उनके शासन कला के गुण आज भी प्रासंगिक है। सुशासन के लिए उनकी शासननीति अनुकरणीय है। लेखक का कहना है कि सफल और महान शासक द्वारा स्वीकार किए गए मूल्य और मान्यताओं का बड़ा महत्व होता है। योग्य धारणा सुशासन और समाधान की ओर ले जाती है।

शिवाजी की शासन कला पर आधारित इस पुस्तक को 6 भागों में बांटा गया है- प्रस्तावना, प्रतिमा निर्माण, शिवाजी शासन के प्रमुख मंत्रालय, संकेत, व्यक्तित्व और जाणता राजा संवाद।

'प्रतिमा निर्माण' के अंतर्गत लेखक ने व्यक्ति के विकसित होकर सफल नायक बनने की यात्रा के चार पायदान बताए हैं। जिसकी चर्चा आरंभ, आकलन, आस्था और अभय शीर्षक के अंतर्गत की है।

आकलन शीर्षक के अंतर्गत लेखक ने बताया है कि छोटे-बड़े सभी कार्यो

शिवाजी शासन के प्रमुख मंत्रालय जिनका पुस्तक में चर्चा किया गया है। वित्त मंत्रालय, गृहमंत्रालय, कृषि मंत्रालय, न्याय व विधि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, व्यापार व उद्योग मंत्रालय, विज्ञान व नौ-परिवहन मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय, भाषा व संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और जन संपर्क।

जो आज के विश्व में ज्वलंत मुद्दे हो गए हैं। जिसे लेकर आज विश्व के देश चिंतित हैं। जिसका अध्ययन हम समकालीन राजनीतिक विषयों के अंतर्गत करते हैं। उन विषय के प्रति शिवाजी उस समय कितना सजग और गंभीर थे, इसकी चर्चा इस पुस्तक में 'संकेत' नामक शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। 'संकेत' में बताया गया है कि शिवाजी के राज्य में वन व पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक, भ्रष्टाचार के लिए भी नीतियां थी।

"शिवाजी ने एक शासकीय आज्ञा-पत्र जारी कर प्रजा में यह आदेश पहुंचाया था कि जहां तक संभव हो, सूखे और मृत हो चुके पेड़ों के ही प्रयोग से विभिन्न प्रकार के कार्य पूरे किए जाएं। जब अत्यंत आवश्यक हो और कोई हरा पेड़ काटना हो तो उसके मालिक की स्वीकृति से ही वह पेड़ काटा जाए।"

आज जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा का भ्रष्टाचार में लिप्त होने का मामला प्रकाश में आया और सरकार किसी भी तरह के जांच के लिए तैयार नहीं है। चूंकि रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और आज यह परिवार शासन में है। ठीक विपरीत शिवाजी के राज्य-व्यवहार में भ्रष्टाचार चाहे वह आचरण में हो या अर्थ तंत्र में बिल्कुल अस्वीकार्य था। शिवाजी भ्रष्टाचार के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, इस सम्बंधन में इस पुस्तक में एक घटना का जिक्र किया गया है कि शिवाजी के मामा मोहित ने रिश्वत ली, यह जानकारी शिवाजी महाराज को मिली तो उन्होंने उसे तत्काल कारागार में डाल दिया और छूटने पर पिता शाहजी के पास भेज दिया। यह पुस्तक उनके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगी जो शासन-सत्ता में किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं। चाहे वह नौकरशाह हो या राजनेता। लेखक स्वयं इस पुस्तक को शासकों के लिए ब्लू प्रिंट बताता है। ■

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको निरन्तर मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

'सामाजिक-आर्थिक विकासः राष्ट्रीय संपदा का आवंटन' विषयक संगोष्ठी संपन्न

भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ ने 'सामाजिक-आर्थिक विकास : राष्ट्रीय संपदा का आवंटन' विषय पर NMDC कन्वेंशन सेंटर में पूरे दिन भर चलने वाला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भूमि, खनिज और जल संसाधन के तीन अलग-अलग सत्र रखे गए। जिसमें देश भर आए विभिन्न शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों एवं शोधार्थियों ने अपने विचार रखे।

पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विषय पर प्रकाश डालते हुए आर्थिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री गोपाल अग्रवाल ने कहा कि ताजा विकास यह दिखाता है कि भारत के मामले में 'ट्रिकल डाउन' का सिद्धांत काम नहीं करता। राष्ट्रीय संपदा, जो देश के सभी नागरिकों का है, कुछ प्रभावशाली लोगों के निजी स्वामित्व में जा रहा है।

सम्मेलन के विशेष सत्र में बोलते हुए पार्टी अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा सुशासन की पार्टी है। श्री गडकरी के अनुसार, 'अंत्योदय' अभी भी पार्टी का दर्शन है। उन्होंने एनडीए शासित राज्यों द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत गांवों में बसता है। उन्होंने कहा कि गांवों में इतनी संकट कभी उत्पन्न नहीं होती यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों एवं दर्शन को चालू रखा जाता।

वर्तमान सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, महंगाई की आलोचना करते हुए कहा कि एनडीए सरकार देश के आर्थिक क्षमता को देखते हुए इसका सही इस्तेमाल करेगी।

भाजपा को राष्ट्रवादी पार्टी कहे जाने पर गर्वान्वित होते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की है और भाजपा नीत सरकार वैश्विक देशों के बीच भारत के स्थान को सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर पार्टी के रुख को भी स्पष्ट किया। उन्होंने बहस के लिए निम्नांकित परिपत्रों को सामने रखा :

- निजी और एनजीओ में रिश्वतखोरी रोक पर दिशानिर्देश
- विकास बनाम विस्थापन - भूमि अधिग्रहण मुद्दा
- जलाधिकार - एक जीवन तत्त्व

पहला तकनीकि सत्र : भू-संसाधन

वर्तमान विकास के बहस में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। भू-स्वामी सहित परियोजना से प्रभावित लोग यह महसूस करने लगे हैं कि इस प्रक्रिया में उनका कोई अस्तित्व नहीं है और इस कारण वे इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं।

इस सत्र की अध्यक्षता श्रीमती सुमित्रा महाजन ने किया। संसद में ग्रामीण विकास मामले की स्थायी समिति की अध्यक्षा होने के नाते उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। उन्होंने भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास बिल 2011 पर कुछ सुझाव भी दिए।

- शारदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री मिलिंडो चक्रवर्ती ने कहा कि सरकार या बाजार अलगाव की स्थिति में भूमि अधिग्रहण से संबंधित को मुद्दे का समाधान नहीं कर सकती है। इसके लिए राजनीति और अर्थशास्त्र को एक साथ आना होगा।
- भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास बिल 2011 पर आरपीएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के श्री एम. आर. माधवन ने कहा कि बिल में सार्वजनिक हित को परिभाषित करना होगा और बिल में उल्लिखित कुछ क्षेत्रों की विस्तृत व्याख्या करनी होगी।
- एसोचैम-कैपिटल मार्केट के अध्यक्ष श्री सुभाष अग्रवाल ने बिल के अन्य प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए भू-स्वामी को मुआवजे पर खास जोर दिया।

- केरल से आए किसान नेता एवं कृषक मुनेत्तम के प्रमुख संचालक श्री वर्गीज थोडु परामबिल ने प्राचीन भारत की भू-व्यस्था को रेखांकित करते हुए किसानों एवं कृषि भूमि को बचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभ्यता का विकास वहीं हो सकता है जहां किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भूमि अधिग्रहण से किसानों के लिए उपजी परेशानियों को उन्होंने रेखांकित किया।
- सत्र की अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन ने बिल को और बेहतर बनाने के लिए स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए तथ्यों पर अपना विचार रखा। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के अनुभवों को भी लोगों के सामने रखा।

द्वितीय सत्र : खनिज संपदा

राज्य सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षक है और उसकी सुरक्षा करना उसका कानूनी दायित्व है। ये संसाधन सार्वजनिक हित के लिए हैं।

वक्ता

- आईआईएम अहमदाबाद के प्रो. समर के. दत्ता ने अपने व्याख्यान में जमीनी स्तर पर इस सेक्टर के नीतियों और क्रियान्वयन में अंतर को बताया। कुछ साल पहल के खादान क्षेत्रों की अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि लाखों करोड़ों की खदान कंपनियां इस गरीबी के समुद्र में फल फूल रही हैं।
- जयपुर के अर्थशास्त्र की प्राध्यापक प्रो. डॉ. ज्योति किरण शुक्ला ने अपनी समालोचना '12वीं पंचवर्षीय योजना में खनिज अन्वेषण एवं विकास कार्यदल पर रिपोर्ट' का जिक्र करते हुए कहा कि रिपोर्ट में दूरदर्शिता की कमी है और विकास का मॉडल कई पारस्परिक कारकों पर आधारित होना चाहिए।
- MMDR Bill, 2011 के अपने विश्लेषण को सामने रखते हुए डॉ. राजकुमार अग्रवाल ने ऐसे बिन्दुओं को सामने रखा, जिसकी अनदेखी बिल में की गयी है।
- बीवीएसएस के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा ने खनिज संपदा और इससे जुड़ी कंपनियों के लिए संविधान में किए गए प्रावधान और वर्तमान कानूनी तंत्र पर अपने विचार रखे।
- खनिज संपदा सत्र के अध्यक्ष के रूप में भाजपा के प्रवक्ता और सांसद श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि खदान आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विषम परिस्थितियों में केन्द्र को कोयले का आवंटन किए पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार को देश के प्रति अपने कर्तव्य का पता नहीं है।

तृतीय सत्र : जल संसाधन

जल, वायु, अग्नि, आकाश एवं पृथ्वी ये जीवन के पांच तत्व हैं। जल मानव अस्तित्व को दर्शाता है।

वक्ता –

- मुख्य भाषण देते हुए आईआईएम, बैंगलोर के सेवानिवृत प्राध्यापक श्री भरत झुनझुनवाला के अनुसार भारत में पानी समस्या कृषि की समस्या है क्योंकि 80 प्रतिशत पानी सिंचाई के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। उन्होंने भंडारण आधारित सिंचाई प्रणाली का भी विरोध किया।
- यमुना बचाओ आंदोलन के सदस्य के रूप में अपने लंबे अनुभवों के आधार पर बोलते हुए श्री दीवान सिंह ने कहा कि दूरदराज के संसाधनों पर निर्भरता के कारण स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसानों की अनदेखी होती है। टिहरी, भाखड़ा नांगल आदि जगहों से दिल्ली में जल की आपूर्ति के कारण यहां के निवासियों का यमुना की अनदेखी की वजह से नाले में तब्दील हो चुकी है।
- दिल्ली जल बोर्ड के कार्यकारी अभियंता श्री प्रकाश गौड़ ने आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर बताया कि दिल्ली में जल वितरण का निजीकरण उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जापान अंतरराष्ट्रीय सहकारी एजेंसी जैसी अंतरराष्ट्रीय संसाथाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ये संस्थाएं विकसित देशों की कंपनियों के लिए बाजार उपलब्ध कराना चाहती हैं।
- जल-युद्ध संस्था के नायक श्री रघु यादव ने भंडारण आधारित सिंचाई के मुद्दे पर श्री झुनझुनवाला से असहमति जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य प्राचीन काल से बाधों का निर्माण करता आया है और आज यह जल का महत्वपूर्ण स्रोत है।
- जल संसाधन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि जल जीवन का महत्वपूर्ण कारक है। इसे आर्थिक वस्तु के रुप में लेना भारतीय दर्शन के खिलाफ है। उनके अनुसार जल के मूल्य निर्धारण का उपभोग पर समान प्रभाव नहीं है।

इसका सबसे ज्यादा असर निम्न आय वर्ग के लोगों पर है, जो पहले ही जरुरी स्तर से कम मात्रा का उपभोग कर रहे हैं लेकिन उच्च आय वर्ग के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। मूल्य निर्धारण सिर्फ इसे गरीबों से दूर करेगी और अमीरों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करेगी।■

पार्टी का मिशन है अन्त्योदय – अंतिम व्यक्ति की समृद्धि : गडकरी

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 18 अक्तूबर को करीमनगर में कहा कि पार्टी ने गरीबी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह उत्तरी तेलंगाना में 'इंटरएक्शन विद पूअर एंड डिपराइण्ड'

अर्थात् 'गरीबों तथा वंचितों के साथ बातचीत' के एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। जिसका आयोजन 'मार्टर्स मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद' ने किया था। उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय सचिव श्री मुरलीधर राव के साथ मिलकर उत्तरी तेलंगाना के वंचित वर्गों के 3000 लोगों के साथ बातचीत की जिनमें किसान, बुनकर, खाड़ी से लौटे लोग, सिंगरेनी के विस्थापित लोग, बीड़ी श्रमिक एवं आदिवासी लोग शामिल थे। यह अपने किस्म का एक ऐसा कार्यक्रम था, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इस कार्यक्रम में देश के सबसे गरीब क्षेत्र के अधिकांश वंचित वर्ग के लोगों ने भाजपा नेताओं से बातचीत की।

श्री गडकरी ने उनकी समस्याओं को सुनकर कहा कि जनसंघ के समय से ही पार्टी का मिशन 'अन्त्योदय' है जिसका मतलब है कि कतार में आखिरी स्थान पर खड़े व्यक्ति को समृद्ध बनाया जाए और यह मिशन दीनदयाल उपाध्याय जैसे संस्थापकों का सपना था।

ग्रामीण निर्धनता की गहराई मापने का इससे बड़ा और क्या पैमाना हो सकता है जब हम देखते हैं कि गांवों में 'आत्महत्याएं' होती हैं। जब हम इस पैमाने को देखते हैं जिसमें उत्तरी तेलगांना देश का सबसे गरीब क्षेत्र दिखाई पड़ता है जिसमें प्रतिवर्ष 2000 किसान आत्महत्याएं करते हैं, हजारों हथकरघा बुनकर आत्महत्या करते हैं, खाड़ी से लौटे विस्थापित कर्ज के बोझ में फंस जाते हैं, और बीड़ी श्रमिकों का पूरा समुदाय गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा दिखाई पड़ता है।

आत्महत्याओं की इस डरावनी संख्या को देखकर केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही एक असंवेदनशील रवैया अपनाए हुए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस बात से जाना जा सकता है जब हम देखते हैं कि गोदावरी की पानी समुद्र में बिना प्रयोग किए बह जाता है और यह बहुमूल्य संसाधन बेकार चला जाता है, जिससे इस नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले किसानों को सिंचाई की सुविधा न मिलने के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सिंचाई की विशेष आर्थिक योजनाओं को उत्तरी तेलंगाना में कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि करीबी, बेरोजगारी और खाड़ी देशों से भारत में लौटने वाले विवश लोगों की संख्या को कम किया जा सके।

मध्यपूर्व की जेलों में 20,000 से अधिक लोग सड़ रहे हैं, परंतु भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार को उनके बारे में जरा सी भी सुध नहीं आती है।

ग्रामीण कर्ज का बोझ बुरी तरह से बढ़ता जा रहा है। इस कर्ज का लगभग 50 प्रतिशत व्यय स्वास्थ्य देखभाल पर किया जाता है। सरकार ने इस स्वास्थ्य देखभाल को पूरी तरह से वापस ले लिया है। और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से लोगों पर स्वास्थ्य देखभाल का पूरा बोझ डाल दिया है। गांवों के लोगों को अपनी जमीनें और अन्य सम्पत्तियां बेचनी पड़ रही है और उन्हें अस्पताल के बिल चुकाने के लिए भारी कर्ज लेना पड़ रहा

है। उत्तरी तेलंगाना में आदिवासियों की जनसंख्या भी काफी अधिक है। बेईमान लोगों ने इन आदिवासियों की आधे से भी अधिक जमीन हड़प ली है। यहां तक कि हाल के (2006) के सेंट्रल ट्राइबल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनने के बाद भी इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

श्री नितिन गडकरी ने इस तरफ भी संकेत दिया कि सिंगरेनी ओपन कास्ट माइन के हजारों विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं किया है। श्री गडकरी ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले विस्थापित सैकड़ों लोगों से उनके तेजी से पुनर्वास करने के लिए सभी आवश्यक उपाए करने का वायदा किया। आज देश के सामने कृषि सम्बन्धी अनेक समस्याएं हैं जिनमें कृषि मुद्रास्फीति, बिजली की कमी, किसानों के लिए कोई निश्चित मूल्य ने होना, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि की बढ़ती कीमतें आदि शामिल हैं।

उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि एनडीए किसानों की कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रहा है जिससे उनकी क्रय शक्ति और प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होगा। भाजपा गरीबी के खिलाफ युद्ध लड़ती रहेगी और यदि वह 2014 में सत्ता में आई तो भाजपा ग्रामीण भारत का पूरा चेहरा बदल देगी जिससे समृद्धि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे।

भाजपा राष्ट्रीय सचिव श्री पी. मुरलीधर राव ने 'अपवंचित वर्ग के चार्टर' का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कल्याणकारी संविधान होने के बावजूद भी स्वतंत्रता की अर्ध-शताब्दी बीत जाने पर भी किसानों को गरीबी और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अंततः हजारों को आत्महत्या का सहारा लेना पड़ता है। ■

अटल डायरी 2013 का विमोचन

20 अक्तूबर को भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जनसंघ की 61वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने अटल डायरी 2013 का विमोचन किया तथा इसकी प्रथम प्रति भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी को भेंट की। भाजपा सांसद श्री बलबीर पुंज और विख्यात अर्थशास्त्री श्री एस. गुरुमूर्ति तथा अन्य विद्वत्जन इस अवसर पर उपस्थित थे। भाजपा द्वारा समर्थित समग्र अटलजी परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशित तथा रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के तत्त्वाधान में सम्पन्न इस सचित्र डायरी का प्रकाशन निरंतर दूसरे वर्ष हो रहा है। यह विलक्षण नई डायरी भाजपा कार्यालय तथा अन्य राज्यों के राजधानियों के कार्यालयों में उपलब्ध है एवं इसे रामभाऊ प्रबोधिनी तथा भाजपा की वेबसाइटों के माध्यम से भी मंगाया जा सकता है। ■

पृष्ठ 16 का शेष...

और सूचना प्रोद्योगिकी (आईटी) का युग आया। किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रामीण गोदामों और कोल्ड स्टोरेज का विकास हुआ। हमारे शासन काल में ही चार-लेन वाले राजपथ बने। रुपया मजबूत हुआ और विदेशी मुद्रा की स्थिति फली-फूली। हमारे योग्य एवं कुशल नेता ने 23 पार्टियों का नेतृत्व किया और गठबंधन धर्म का निर्वाह कराते हुए एक स्थिर सरकार प्रदान की। आपकी सरकार ने गठबंधन धर्म का अनुसरण नहीं किया। यही वजह है कि आपकी सरकार का बायां हाथ कोई प्रस्ताव रखता है तो दायां हाथ उसका विरोध करता है और अंततः आपका मन ध्वस्त कर देता है। आपकी सरकार कुछ इस प्रकार की है- एक कदम आगे बढ़ो, तीन कदम पीछे हटो और फिर आपकी स्थिति अनाड़ियों वाली बन जाती है।

यही कारण है कि लोग आपसे नाराज हैं। एक के बाद एक चुनाव, एक राज्य के बाद दूसरा राज्य, एक शहर के बाद दूसरा शहर- हर जगह आपकी पार्टी हारती चली जाती है। एक घोटाला सामने आता है तो दूसरा घोटाला खड़ा हो जाता है। आपकी सरकार हर दोषी को बचाने की पूरी-पूरी कोशिश करती है। आज देश के लोग आपकी पार्टी को उखाड़ फेंकने के अवसर की तलाश में है। शायद यही वजह है कि आपने सुधारों की बात सोची। यदि आपकी पार्टी के लिए सुधार इतने ही महत्वपूर्ण थे तो ये अब क्यों हो रहे हैं और पिछले 8 वर्षों में इनके लिए कोई पहल क्यों नहीं की गई? आप कर क्या रहे थे?

अपने भाषण की समाप्ति पर श्री नायडू ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी को कठघरे में खड़ा करने, यूपीए घोटालों का पर्दाफाश करने का आह्वान करते हुए कहा कि महंगाई, कृषि संकट और एनडीए की उपलब्धियों को लोगों के सामने लाएं। ■

कांग्रेस को लोगों के साथ धोखा करने की आदत है : नरेंद्र मोदी

बेलगाम महंगाई पर साल 2009 में चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करने में नाकाम रहने के लिए यूपीए की आलोचना करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। श्री मोदी ने कहा कि अगर यूपीए उनसे कॉम्पिटिशन करना चाहती है तो विकास के मुद्दे पर करे।

श्री मोदी ने 15 अक्टूबर 2012 को जसदण में पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि सोनिया गांधी ने गुजरात के विकास की आलोचना की लेकिन सत्ता में आने के 100 दिन के भीतर महंगाई को कम करने के चुनाव पूर्व के वादे पर कभी कुछ नहीं कहा।

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम रही है। श्री मोदी राजकोट में तीन अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा किसानों की रैली को संबोधित किए जाने का उल्लेख कर रहे थे।

'झूठ का प्रचार करने' के कांग्रेस के आरोपों के संबंध में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा की झूठ फैलाने में दिलचस्पी नहीं है और गुजरात में मेरी सरकार द्वारा किया गया विकास प्रत्यक्ष है।

कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यूपीए भाजपा की गुजरात सरकार के साथ कॉम्पिटिशन करना चाहती है तो इसे विकास के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए।

श्री मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि आप दिल्ली में सौदों के बारे में सुनते हैं लेकिन मैं कोई सौदेबाजी नहीं करता क्योंकि न तो मुझे बेटा है और न ही दामाद। छह करोड़ गुजराती मेरे परिवार हैं और मैं गुजरात का विकास करूंगा।

***

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को मुफ्त बिजली देने जैसे वादे को झूठा बताते हुये फिर से कांग्रेस पर लोगों के साथ 'धोखा' करने की बात दुहरायी।

धोलेरा को नया जिला बनाने के राज्य सरकार के निर्णय पर भाजपा की धोलेरा इकाई की ओर से आयोजित रैली में श्री मोदी ने कहा, 'अगर कोई गलती करता है, तो लोग उसे माफ कर देते है, लेकिन अगर कोई धोखा देता है क्या लोग उसे माफ कर सकते हैं?'

श्री मोदी ने कहा, 'कांग्रेस को लोगों को धोखा देने के लिए जाना जाता है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था लेकिन सत्ता में चार साल रहने के बावजूद भी इसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।'

मुख्यमंत्री ने कहा, 'उन्होंने 2009 में चीजों की कीमतें 100 दिन में कम करने का वादा किया था, लेकिन चीजो के दाम अभी भी बढ़ रहे हैं। क्या यह धोखा नहीं है..? ■

नरेंद्र मोदी से मिले ब्रिटिश उच्चायुक्त

गत 22 अक्टूबर 2012 को ब्रिटिश उच्चायुक्त श्री जेम्स बेवन ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री मोदी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि गुजरात के साथ रिश्ते मजबूत करने और सक्रिय साझेदारी के लिए ब्रिटेन की सरकार के कदम का स्वागत करता हूं।

श्री बेवन एक छोटे शिष्टमंडल के साथ श्री मोदी से मुलाकात के लिए पूर्वाह्न करीब 11 बजे गांधीनगर में गुजरात सचिवालय परिसर पहुंचे। यह बैठक करीब 50 मिनट तक चली। श्री नरेंद्र मोदी और श्री जेम्स बेवेन बेहद गर्मजोशी से मिले। मुलाकात के बाद बेवन राज्यपाल श्रीमती कमला बेनीवाल से मिलने गये।

ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने दूत जेम्स बेवन से गुजरात जाकर श्री मोदी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने तथा आपसी हित के अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सहयोग के अवसर तलाशने के लिए कहा था।

गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव : नितिन गडकरी

गत 21 अक्तूबर 2012 को इंदौर स्थित आनंद मोहन माथुर सभाग्रह में भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ व फ्रेन्डस ऑफ बीजेपी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'देश की 'आर्थिक नीतियां चुनौतियां और समाधान' पर केन्द्रित परिसंवाद में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतिन गडकरी ने कहा कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने देश में रामराज्य की स्थापना का सपना देखा था। पं. जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास के लिए, जो विदेशी मॉडल अपनाया, उसका खामियाजा देश को 65 वर्षों तक भुंगतना पड़ा। पं. नेहरू ने देश से गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा था। इंदिरा गांधी ने उसे ही आगे बढ़ाया। बाद में राजीव गांधी, सोनिया गांधी और यहां तक कि वह अधूरा लक्ष्य पूरा करने के लिए राहुल गांधी को भी वही नारा दोहराना पड़ रहा है। इस विफलता का कारण गांव की उपेक्षा, गरीब, किसान मजदूर को सरकार के राडार से हटा देना रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए दूरदृष्टि और राजनैतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश में कृषि के क्षेत्र में 18 प्रतिशत विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की प्रशंसा की और कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुझसे प्रदेश में कृषि की तरक्की के बारे में चर्चा की थी तब मध्यप्रदेश में कृषि की विकास दर 2.4 प्रतिशत थी और प्रदेश में 7 लाख हैक्टेयर पर सिंचाई होती थी, मैंने कहा था कि यदि सिंचाई की क्षमता में वृद्धि होगी किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा तो कृषि की विकास दर अपने आप बढ़ जायेगी। मध्यप्रदेश सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया। सिंचन क्षमता 22 लाख हैक्टेयर हुई और कृषि की विकास दर 18.89 प्रतिशत हो गयी है।

उन्होंने विदर्भ में 10 हजार किसानों की आत्महत्या, आंध्र में बुनकरों की हताशा के लिए केन्द्र सरकार की गलत नीतियों को उत्तरदायी बताया और कहा कि देश में योजना का पुनरावलोकन आवश्यक है। क्योंकि पिछली 11 योजनाओं में हम देख चुके है कि देश का गरीब और गरीब होता गया एवं धनवान अरबपति हुआ है। उन्होंने कहा कि नीतियां समय के अनुसार गतिशील बनायी जाना चाहिए। उन्होंने आदर्श राज्य के रूप में रामराज्य की कल्पना को समीचीन बताया और कहा कि छत्रपति शिवाजी ने उसका अनुसरण कर इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित किया है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अधिकतम उत्पादन में अधिकतम व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन देश में न तो ऐसा हुआ है और न हो पाया है। इसके बारे में हमें संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके लिए देश में दृष्टि-पत्र बनाया जाना चाहिए और उस पर अमल किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि देश में 68 सेक्टर में उन्होंने कार्ययोजना बनाकर कार्य आरंभ किया है।

श्री गडकरी ने कहा 65 वर्षों में हम वांछित प्रगति नहीं कर पाये है और लक्ष्य में पिछड़ गये है इसका कारण गलत नीतियां और भ्रष्टाचार है। उन्होंने

मध्यप्रदेश विशेष रूप से इंदौर में हुए विकास कार्यो की सराहना की और कहा कि हमें देश के लिए कुछ करना हैं तो राजनीति की व्याख्या बदलना पड़ेगी। पावर पॉलिटिक्स पर टिप्पणी करना समय की बर्बादी है। सभी को मिलजुल कर देश की तरक्की के बारे में 'स्ट्रांग पॉलिटिक्ल डेव्लपमेंट ओरिऐंटेड बिल' से काम करना होगा। कमियों पर खुलकर चर्चा करना पड़ेगी और गुणात्मक परिवर्तन के लिए कमर कसनी पड़ेगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा ने कहा कि इन्दौर और ताई विकास के पर्याय बन चुके है, ताई ने अपने नाम और कार्य को सार्थक किया है। आज इन्दौर पर पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें है। ताई ने संवाद के जरिये इंदौर के विकास में अहम योगदान दिया है। विकास के लिये संवाद आवश्यक है, जनता और सरकार के बीच कार्यकर्ता संवाद सेतु का कार्य करें और सरकार की विकासोन्मुखी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिये सामाजिक संगठनों, धार्मिक गुरूओं और समाज के प्रमुखों से संपर्क कर विकास में सहयोगी बनायें। सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि इन्दौर ने अपने बल पर विकास किया है। इन्दौर की जागरूक जनता ने विकास के लिये हमेशा योगदान दिया है। इन्दौर कपड़ा व्यवसाय और ट्रेडिंग के लिये पूरे देश में विख्यात था, लेकिन आर्थिक संकट के चलते ये व्यवसाय सिमट गया है, लेकिन जनसहयोग और विकास के चलते इन्दौर ने आईटी हब के रूप में अपने आप को विश्व के नक्शे में दर्ज कराया है।

भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ललित पोरवाल, मिलिंद महाजन, राजेश अग्रवाल, अशोक डागा ने अतिथियों का स्वागत किया। ■

यूपीए शासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला : डॉ. जोशी

भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार 'मंहगाई मिटाओ- कांग्रेस हटाओ- देश बचाओ अभियान' की शुरूआत की। गत 11 अक्तूबर 2012 को राजधानी लखनऊ में प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर अभियान की शुरूआत करते हुए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेई, वरिष्ठ नेता एवं सांसद लालजी टण्डन व संगठन महामंत्री राकेश जैन भी उपस्थित रहे।

लखनऊ में भ्रष्टाचार महंगाई मिटाओ-कांग्रेस हटाओ-देश बचाओ अभियान' के तहत प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार के कार्यकाल में देश में भ्रष्टाचार व घोटालों को बढ़ावा मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स, 2जी स्पेक्ट्रम और कोल ब्लॉक आवंटन सहित घोटालों की लम्बी फेहरिस्त यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार व घोटालों में घिरी केन्द्र सरकार के मंत्री कैग जैसी सवैधानिक संस्था पर भी हमले कर रहे हैं। डॉ. जोशी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे केन्द्र की यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार व घोटालों के खिलाफ व्यापक स्तर पर जनजागरण का अभियान चलाये। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाये जाने वाले अभियान को सफल बनाने का जिम्मा सौंपते हुए संकल्प दिलाया कि भारत को कांग्रेस के भ्रष्टाचार व कुशासन से मुक्त करेंगे, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोकतंत्रिक ढंग से संघर्ष करेंगे। 21वीं शताब्दी को हम भारत की शताब्दी बनाएंगे।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेई ने कहा कि देश की जनता बेतहाशा बढ़ती मंहगाई से त्रस्त है। पेट्रोल डीजल सहित आम जन की जरूरत की रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में हुई बेतहाशा मूल्य वृद्धि से गरीब जनता कराह रही है। केन्द्र की यूपीए सरकार के काले कारनामों, भ्रष्टाचार व घोटालों ने रिकॉर्ड बनाया है। जनता का धन सरकार में बैठे लोगों ने भ्रष्टाचार व घोटालों को अंजाम देकर लूट लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन चला कर देश को यूपीए सरकार के कुशासन से मुक्त कराये। कार्यक्रम को वरिष्ठ नेता एवं सांसद लाल जी टण्डन ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री राकेश जैन, सांसद कुसुम राय, प्रदेश मंत्री आशुतोष टण्डन "गोपाल", संतोष सिंह, पूर्व सांसद रामनरायण साहू, क्षेत्रीय संयोजक शेष नारायण मिश्रा, पूर्व विधायक विद्यासागर गुप्ता सहित कई अन्य प्रमुख नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। ■

दिल्लीभर के धरना-प्रदर्शनों में 50 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया

जनविरोधी, लूटखोर दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ भाजपा का 40 दिवसीय जन आंदोलन प्रारंभ

बिजली के बढ़े दाम तुरंत वापस लेने और जनविरोधी दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ दिल्ली भाजपा का 40 दिवसीय सतत् आंदोलन 14 अक्टूबर से 50 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं के सड़क पर उतर कर जनजागरण और सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करने के साथ शुरू हो गया। इस आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के प्रदर्शनों में जाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह शीला सरकार के पुतले फूंके और घर-घर जाकर दिल्लीवासियों से अपील की कि वे भ्रष्ट शीला सरकार को उखाड़ फेंके।

रिची रिच के सामने हजारों की संख्या में धरना-प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार, सरकार न रहकर गैंग ऑफ वासेपुर बन गई है।

इसका हर नेता, हर मंत्री जन धन की खुली लूट में व्यस्त है। प्रधानमंत्री की भूमिका धृतराष्ट्र की हो गई है। उन्हें न कुछ दिखाई देता है न सुनाई देता है और न ही वे खुली लूट के खिलाफ कुछ बोल पाते हैं। दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कई धरना प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र और दिल्ली की कांग्रेस सरकारें तानाशाह हो गयी हैं। वे अपने खिलाफ एक भी शब्द सुनना नहीं चाहती हैं। दिल्ली तथा देश की जनता को अब सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक आजादी की एक नई लड़ाई लड़नी होगी। राष्ट्रीय महामंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि कांग्रेस सरकारों ने आम जनता का जीवन दूभर कर दिया है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, बिजली, पानी, परिवहन के दाम बढ़ा दिये गये हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। हर तरफ जनता को खुले आम लूटा जा रहा है। राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल ने कहा कि जनता की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। अब लोगों के पास एक ही रास्ता बचा है कि वे भ्रष्ट, निकम्मी और लूटखोर कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट दें। प्रदेश के सह-प्रभारी श्री रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस के अत्याचारों को सहने के लिये अब तैयार नहीं है। इस मौके पर प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दिन पूरे हो गये हैं। अब इस निकम्मी और लूटखोर सरकार को जाना ही होगा।

बाहरी दिल्ली के जिलाध्यक्ष संसार सिंह ने आज रोहिणी सेक्टर-4 एमसीडी के वार्ड संख्या 45 तक कार्यकर्ताओं और आम जनता को साथ लेकर सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों पुरुष और महिलायें शीला दीक्षित इस्तीफा दो, बिजली पानी के दाम घटाओ आदि नारे लगाते हुये चल रहे थे। पार्षद संजना सिंह ने महिलाओं की टोली की अगुवाई की।

इन धरना-प्रदर्शनों में रिचीरिच के सामने श्री विजेन्द्र गुप्ता, गढ़ी गांव में प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री विजय गोयल, डॉ. मुंजे चौक पर श्री धर्मेन्द्र प्रधान, सुश्री वाणी त्रिपाठी, बद्रीनाथ मंदिर पार्क में डॉ. हर्ष वर्धन, पीरागढ़ी चौक पर श्री रामेश्वर चौरसिया, प्रहलादपुर चौक पर श्री थावरचंद गहलोत, श्री रमेश बिधूड़ी, कश्मीरी बाग में श्रीमती मीनाक्षी लेखी, बी-ब्लॉक, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास श्री मांगेराम गर्ग, खजूरी चौक पर श्री पवन शर्मा, श्री प्रवेश वर्मा, उत्तम नगर टर्मीनल पर श्री विजय जॉली, श्री आशीष सूद, पीपल चौक खानपुर में श्रीमती विशाखा शैलानी आदि नेताओं ने संबोधित किया। ■